RNI No. : TNHIN/2013/5252 ■ वर्ष - 13 ■ अंक - 123 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » गुरुवार » 27-11-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 आप क्रिकेट को हल्के में नहीं ले सकते, हमें बेहतर बनने की जरूरत है : पंत

6 आक्रामक साजिशों के बीच संविधान की असल ताकत

7 धर्मेंद्र लीजेंड हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता : नीतू चंद्रा

फर्स्ट टेक

अहमदाबाद में होंगे 2030 राष्ट्रमंडल खेल

ग्लास्गो/भाषा। अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान चुने जाने की औपचारिक घोषणा बुधवार को यहां हो गई जिससे दो दशक बाद भारत में इन खेलों की वापसी होगी और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की देश की आकांक्षा को भी बल मिलेगा । राष्ट्रमंडल खेलों का यह सौवां वर्ष भी होगा । पहली बार ये खेल कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में हुए थे । पिछले महीने 'कॉमनवेल्थ स्पोर्ट (राष्ट्रमंडल खेल)' के कार्यकारी बोर्ड द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष में प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद की सिफारिश के बाद 74 सदस्यों की आमसभा के लिए भारत की बोली पर मुहर लगाना महज एक औपचारिकता थी। भारत ने पिछली बार 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी।

देश की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है : गिनी-बिसाऊ के सैनिक

बिसाऊ/एपी। गिनी-बिसाऊ के सैनिकों ने बुधवार को सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। देश के राष्ट्रपति भवन के निकट गोलीबारी की खबरों के बाद सैनिकों ने यह जानकारी दी। सैन्य उच्च कमान ने सरकारी टेलीविजन पर एक बयान में कहा कि उसने गिनी-बिसाऊ गणराज्य के राज्य की पूर्ण शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। देश की सैन्य उच्च कमान के प्रवक्ता डिनिस एन'तचमा ने कहा कि यह कदम हमारे देश को अस्थिर करने के लिए चल रही एक योजना के जवाब में उठाया गया है।''

41 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक करोड़ 19 लाख रुपए के इनामी 32 नक्सलियों समेत 41 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में आज 41 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी और धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड डिवीजन के नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति ने दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव स्थापित की है। पुलिस, सुरक्षाबलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के जागरुक नागरिकों के सामूहिक तथा समन्वित प्रयासों से हिंसा और भय की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में बदलने में बड़ी सफलता मिली है।

27-11-2025 सूर्यास्त 5:39 बजे | 28-11-2025 सूर्योदय 6:13 बजे

BSE	NSE
85,609.51	26,205.30
(+1,022.50)	(+320.50)

सोना	चांदी
13,170 रु.	176,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

चत्वारि कालखण्ड

सतयुग से त्रेता युग तक था,
सच्चे लक्षण का कालखण्ड।
द्वापर से कलयुग आदि रहा,
हित संरक्षण का कालखण्ड।
आजादी तक का समय रहा,
शोषण भक्षण का कालखण्ड।
नब्बे के दशक बाद का है,
बस आरक्षण का कालखण्ड।।

भारत-साइप्रस आर्थिक संबंधों में विस्तार की अपार संभावनाएं : मुर्मू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि भारत-साइप्रस आर्थिक संबंधों में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान के मुताबिक, साइप्रस से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मजबूत संसदीय परंपराओं से जुड़े घनिष्ठ साझेदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत साइप्रस के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है, जो साझा रणनीतिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान पर आधारित है।

साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष एनीटा डेमेट्रियू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। मुर्मू ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और साइप्रस के बीच राजनीतिक संपर्क, आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत-साइप्रस आर्थिक संबंधों में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी सराहना की। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुर्मू ने इस बात की सराहना की कि डेमेट्रियू साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की पहली महिला और सबसे युवा अध्यक्ष हैं।

निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन चुका है भारत, ले रहा बड़े फैसले : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की निवेश क्षमता पर बल देते हुए बुधवार को कहा कि सुधारों को तेजी से लागू कर रहा भारत अब बड़े फैसले लेता है और निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में फ्रांसीसी विमानन कंपनी सैफरान के विमान इंजन एमआरओ संयंत्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है और राष्ट्रीय एकल-खिड़की व्यवस्था से विभिन्न अनुमोदन को एक मंच पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार, चेहरा-रहित कर आकलन, नए श्रम कानून और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के आने से शासन पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बना है। उन्होंने कहा, ''इन कोशिशों से भारत को अब एक भरोसेमंद साझेदार, एक बड़े बाजार और उभरते विनिर्माण केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। आज भारत में तेजी से वृद्धि हो रही है, सरकार स्थिर है, सुधार पर ध्यान देने वाली सोच है, युवा प्रतिभाओं की भरमार है और एक बड़ा घरेलू बाजार है। सबसे जरूरी बात, भारत में निवेश करने वालों को देश सिर्फ निवेशक नहीं, बल्कि विकसित भारत के सफर में सह-निर्माता और हितधारक मानता है।''

प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में फ्रांसीसी विमानन कंपनी सैफरान के विमान इंजन एमआरओ संयंत्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया।

तेजी से बढ़ रहा है नागर विमानन क्षेत्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का नागर विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और देश का घरेलू बाजार दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने 1,500 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि विमानों के रखरखाव, मरम्मत एवं देखभाल यानी एमआरओ का करीब 85 प्रतिशत काम विदेशों में होने से लागत बढ़ती है और विमानों को लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है। इस चुनौती को देखते हुए सरकार भारत को वैश्विक एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।

मोदी ने कहा कि सैफरान का इंजन एमआरओ केंद्र देश में पहली बार किसी वैश्विक विमान कंपनी द्वारा विस्तृत सर्विसिंग के लिए स्थापित किया जा रहा है।

सत्ता को लेकर खींचतान खत्म नहीं करा पा रहे हैं तो

सिद्धरामय्या इस्तीफा दें, चुनाव की घोषणा करें : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भाजपा ने मखौल उड़ाते हुए कहा कि इस बार बेलगावी के बजाय दिल्ली में विधानसभा सत्र आयोजित करना उचित होगा।

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को संकेत दिया कि मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव की घोषणा करनी चाहिए यदि उनकी पार्टी उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के साथ सत्ता को लेकर जारी खींचतान खत्म नहीं करा पा रही है।

मुख्यमंत्री और शिवकुमार के बीच खींचतान के मद्देनजर भाजपा ने कहा कि यह मुद्दा संकटग्रस्त लोगों, खासकर किसानों को प्रभावित कर रहा है, जो पिछले एक महीने से आंदोलन पर हैं। भाजपा ने कहा कि उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि

सत्तारूढ़ कांग्रेस को 8 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए इस स्पष्टता के साथ बेलगावी आना चाहिए कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब किसान संकट में हैं और राज्य सरकार से जवाब और मुआवज़ा मांग रहे हैं, तो उन्हें (कांग्रेस को) किसानों के लिए उचित मुआवजा पैकेज के साथ बेलगावी आना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें सत्र स्थगित कर देना चाहिए या अगर वे स्थिति को संभालने में असमर्थ हैं, तो इस्तीफा दे दें और चुनाव की घोषणा कर दें।

शिकारीपुरा से विधायक ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के भीतर अंदरूनी कलह जारी है और यह कोई छिपी बात नहीं है कि पिछले एक महीने से कैबिनेट मंत्री और विधायक कर्नाटक की बजाय नई दिल्ली में अधिक समय बिता रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि सिद्दरामय्या और शिवकुमार भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने का समय लेने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जो पांच दशकों के अनुभवी नेता हैं, असहाय दिखाई दिए और कहा कि केवल राहुल गांधी को ही इस पर फैसला लेना है।

मनमाफिक मतदाता सूची तैयार कर रही भाजपा : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर पिछड़े,दलित, वंचित एवं गरीब मतदाताओं के नाम हटाकर अपनी मनमाफिक मतदाता सूची तैयार कर रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की हत्या के लिए जम्मेदार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के एक बीएलओ का वीडियो साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, दबाव, धमकी और नतीजा? आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े दलित वंचित गरीब वोटरों को सूची से हटाकर भाजपा अपनी मनमाफिक मतदाता सूची तैयार कर रही है।'' उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग 'लोकतंत्र की हत्या' के लिए जिम्मेदार है।

हसीना को प्रत्यर्पित किए जाने के बांग्लादेश के अनुरोध पर गौर किया जा रहा : भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने बुधवार को कहा कि वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित किए जाने के अनुरोध पर गौर कर रहा है और वह उस देश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हसीना (78) को पिछले सप्ताह ढाका में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मानवता के

विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के लिए यह सजा सुनाई गई।

अवामी लीग की नेता हसीना पिछले साल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। हसीना के सहयोगी और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी इसी तरह के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी। अदालत के फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत को पत्र भेजकर उनके प्रत्यर्पण की मांग की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस अनुरोध पर न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता समेत लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संविधान की आत्मा ने प्रमाणित किया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा : उपराष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को सभी से 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और कहा कि हमारे संविधान की आत्मा ने प्रमाणित कर दिया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा।

संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संवाद, बहस और चर्चा को अपनाएं। उन्होंने कहा, ''लोगों के योगदान के बिना कोई भी देश ऐसे ही महान नहीं बन सकता। हमें कर्तव्यबोध के साथ अपनी-अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी।''

उपराष्ट्रपति ने कहा, ''इस दिन हमारे शानदार संविधान के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यह है कि हम इसके मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लें।''

जन प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, ''चाहे संसद हो या राज्य विधानसभाएं या स्थानीय निकाय, यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि हम लोगों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संवाद, बहस और चर्चा को अपनाएं।''

उपराष्ट्रपति ने कहा, ''हमारे संविधान निर्माताओं की इसी भावना के अनुरूप हमें अब इस अमृत काल में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए।''

मुंबई हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि;

आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने पर गृह मंत्री अमित शाह का जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/नई दिल्ली/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को बुधवार को पुष्पांजलि अर्पित की।

हमले की 17वीं बरसी पर अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने को कहा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति को रेखांकित किया।

राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री आशीष शेलार ने भी दक्षिण मुंबई में

पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

शाह ने 'एक्स' पर अपने

संदेश में कहा कि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। उन्होंने कहा, ''मुंबई आतंकी हमले का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं और इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति स्पष्ट है, जिसे पूरा विश्व सराह रहा है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों को व्यापक समर्थन दे रहा है।''

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 'एक्स' पर शहीदों को याद करते हुए कहा कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों की बरसी पर, मैं उन वीर सैनिकों को नमन करती हूं जिन्होंने हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक याद करता है।

मुर्मू ने कहा, ''आइए! हम हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। आइए! हम एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ प्रगति के पथ पर एक साथ आगे बढ़ें।''

रथोत्सव

कुक्के सुब्रह्मण्य में चंपा षष्ठी रथोत्सव के दौरान बुधवार को हजारों श्रद्धालु दिव्य रथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा।

अच्छे नेतृत्व के बिना बेहतरीन संविधान भी विफल हो जाता है : मुख्यमंत्री नायडू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि सबसे अच्छा संविधान भी खराब नेतृत्व में विफल हो जाता है। उन्होंने बी.आर. आंबेडकर के इस विचार का हवाला दिया कि अच्छे लोग प्रणालीगत खामियों के बावजूद सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं।

'संविधान दिवस' समारोह के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में नायडू ने सभी 175 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे छात्रों के एक सत्र को संबोधित किया तथा उनके आत्मविश्वास और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित यथार्थवादी माहौल की सराहना की। इस सत्र का आयोजन विधानसभा की कार्यवाही की तर्ज पर किया गया था।

विधायकों की भूमिका निभा रहे छात्रों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, संविधान चाहे कितना भी महान क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो परिणाम बुरे ही होंगे। इसके विपरीत, संविधान चाहे कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, तो परिणाम सकारात्मक ही होंगे। उन्होंने छात्रों की सराहना की कि उन्होंने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ विधानसभा का माहौल तैयार किया, जो संविधान की भावना और भावी पीढ़ियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

आईटी मंत्री नारा लोकेश और अन्य अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने छात्रों को विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रदर्शन करते देखा। उन्होंने कहा कि छात्रों में संवैधानिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गया था।

कांग्रेस नेताओं ने मॉस्क पहनकर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विरोध दर्ज कराया

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के कई वरिष्ठ नेता वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए बुधवार को मॉस्क पहनकर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक संवाददाता सम्मेलन में पहुंचे तथा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आह्वान किया कि वह शहर को इस ''स्वास्थ्य आपातकाल'' से बाहर निकाले।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ और कई नेताओं ने इस अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बाद में दिल्ली सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार को ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

दिल्ली पिछले कई दिनों से लगातार खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रही है। देवेंद्र यादव ने कहा कि वे प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा, ''जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे नेता यहां ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बैठे हैं। यह अभी के लिए प्रतीकात्मक है, लेकिन दिल्ली जिस स्थिति में है, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हर कोई जीवित रहने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखेगा।''

सैफरान भारत के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की इंजन प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण को तैयार : सीईओ

हैदराबाद/भाषा। वैश्विक रक्षा एवं विमानन कंपनी सैफरान ने बुधवार को कहा कि फ्रांसीसी सरकार के पूर्ण समर्थन से वह भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए इंजन प्रौद्योगिकी का पूर्ण हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सैफरान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ओलिवर एंड्रीस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कंपनी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ इंजन के सह-विकास पर तकनीकी एवं वाणिज्यिक चर्चाएं करेगी। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जिसके लिए कंपनी इंजन प्रौद्योगिकी का पूरी तरह हस्तांतरण करने का प्रस्ताव दे रही है।

एंड्रीस ने कहा, ''फ्रांस सरकार के पूरे समर्थन से हम अगले लड़ाकू विमान इंजन के विकास के लिए इंजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।''

भारत ने पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) के पांच प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना है।

दुर्लभ खनिज चुंबक के विनिर्माण प्रोत्साहन के लिए 7,280 करोड़ रु. की योजना को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने बुधवार को दुर्लभ खनिज स्थायी चुंबकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इस कदम से देश की चीन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। यह खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैमानिकी और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 'ठोस दुर्लभ खनिज स्थायी चुंबकों के विनिर्माण की प्रोत्साहन योजना' को स्वीकृति प्रदान की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''यह योजना दुर्लभ खनिज स्थायी चुंबक के विनिर्माण को बढ़ावा देगी। इसका

उद्देश्य 6,000 टन प्रति सालाना क्षमता सृजित करना है।'' यह योजना एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगी। इसमें दुर्लभ खनिज ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्र धातुओं में और मिश्र धातुओं को तैयार चुम्बकों में परिवर्तित करना शामिल है। इस प्रोत्साहन योजना के तहत कुल उत्पादन क्षमता को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पांच लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 1,200 टन प्रति वर्ष की क्षमता मिलेगी। इस योजना की अवधि परियोजना आवंटन तिथि से सात वर्ष की होगी। इसमें दो साल का समय दुर्लभ खनिज स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के संयंत्र स्थापित करने और अगले पांच वर्ष बिक्री पर प्रोत्साहन देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के लिए कुल 7,280 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें पांच वर्षों के लिए आरईपीएम की बिक्री से संबंधित 6,450 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन और 6,000 टन प्रति वर्ष आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। प्रत्येक लाभार्थी को 1,200 टन सालाना तक की क्षमता आवंटित की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक अनुप्रयोगों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की तेजी से बढ़ती मांग के कारण, भारत में आरईपीएम की खपत 2025 से 2030 तक दोगुनी होने की संभावना है।

प्रदूषण के कारण डिजिटल आधार पर सुनवाई पर कर रहे विचार: प्रधान न्यायाधीश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंभीर वायु प्रदूषण के कारण उच्चतम न्यायालय की सुनवाई केवल डिजिटल तरीके से करने की संभावना पर विचार करते हुए कहा कि एक दिन पहले जब वह एक घंटे की सैर पर गए थे तो उन्होंने खुद को अस्वस्थ महसूस किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह बार से परामर्श के बाद निर्णय करेंगे, हालांकि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल तरीके से सुनवाई की अनुमति देने का विचार अदालत में रखा गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह टिप्पणी तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत में कीं, जब आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी।

द्विवेदी ने कहा, ''मुझे प्रदूषण से दिक्कत है... कृपया मेरे सहकर्मी को नोट लेने की अनुमति दें। मैं अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि सुबह की सैर पर जाने के बाद से उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दी जाए, मेरी तबियत ठीक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सहमति जताते हुए कहा, ''इस उम्र में, हम इस खराब हवा में सांस ले रहे हैं, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400-500 है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कल मैं एक घंटे टहलने गया था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। इसके बाद, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वकीलों को सुनवायी के लिए भौतिक पेशी से छूट देने की संभावना पर विचार किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''अगर मैं कोई फैसला लेता हूं, तो हम पहले बार को भरोसे में लेंगे। हम वकीलों और मुकदमा लड़ने वालों को होने वाली मुश्किलों को देखेंगे... अगर हमें कोई प्रस्ताव मिलता है, तो हम कुछ करेंगे। मैं शाम को पदाधिकारियों से मिलूंगा और कुछ कदम उठाऊंगा।'' अभी, शीर्ष अदालत 'हाइब्रिड मोड' में काम करती है जिसके तहत सुनवायी भौतिक और डिजिटल, दोनों तरीकों से होती है। बुधवार सुबह राजधानी में हवा की गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज की गई क्योंकि एक्यूआई 335 थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है।

'भूमि पुत्रों को नौकरियों में दरकिनार करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं होंगी'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पालघर/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि पालघर जिले में बन रही वधावन बंदरगाह परियोजना में स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आगाह कि इस विशाल परियोजना में ऐसे लोगों को उनके समुचित रोजगार से वंचित करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बंदरगाह परियोजना से 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

फडणवीस दो दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों के लिए पालघर जिले के डहाणू और पालघर कस्बों में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस ने कहा, वधावन बंदरगाह दुनिया के शीर्ष बंदरगाहों में से एक बनने जा रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला बंदरगाह होगा और इससे लगभग 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। फडणवीस ने कहा, मैंने प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वधावन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये 10 लाख नौकरियां भूमि पुत्रों एवं पुत्रियों को मिलेंगी... 56 कंपनियों ने पहले ही समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया हैं। उन्होंने कहा, स्थानीय निवासियों को नौकरियों में दरकिनार करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई पालघर या डहाणू के लोगों को उनके वाजिब रोजगार से वंचित करने की कोशिश करेगा, तो यह देवेंद्र भाऊ वहां जाकर उन्हें बता देगा कि यह सब नहीं चलेगा।

भारत में अपने ग्राहकों के लिए चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने का इरादा: टेस्ला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता टेस्ला ने बुधवार को कहा कि वह भारत में ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों के अनुरूप चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने पर काम कर रही है और देश के सभी प्रमुख शहरों को इसके तहत लाने का लक्ष्य रखती है। कंपनी पहले ही दिल्ली और मुंबई में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। कंपनी ने अब गुरुग्राम के ऑर्किड बिजनेस पार्क में पहला टेस्ला सेंटर शुरू किया है जहां खुदरा बिक्री, आपूर्ति और चार्जिंग की सभी सुविधाएं एक ही केंद्र से उपलब्ध होंगी। टेस्ला इंडिया के महाप्रबंधक शरद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी सुपरचार्जर नेटवर्क और घरेलू चार्जिंग समाधान दोनों तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और मुंबई में तीन सुपरचार्जर पहले से कार्यरत हैं और गुरुग्राम में एक अन्य सुपरचार्जर लगाया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे महानगरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बदलाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टेस्ला अब तक दुनिया भर में 80 लाख से अधिक गाड़ियां बेच चुकी है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 3.2 करोड़ टन की कमी आई है।

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के नए दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली/भाषा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 'अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति योजना' के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है और संस्थानों की जवाबदेही को सख्त किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है और इसके तहत भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूरी 'ट्यूशन फीस' और शैक्षणिक भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

संशोधित वित्तीय मानकों के तहत केंद्र सरकार निजी संस्थानों के छात्रों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पूरी ट्यूशन फीस और अप्रतिदेय शुल्क प्रदान करेगी, जिसकी सीमा प्रति वर्ष दो लाख रुपए निर्धारित की गई है। छात्रों को पहले वर्ष में 86,000 रुपए और इसके बाद के वर्षों में 41,000 रुपए का शैक्षणिक भत्ता भी दिया जाएगा, जो आवास, किताबें और लैपटॉप जैसे खर्चों को कवर करेगा। लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय या राज्य योजनाओं से समान छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति उन अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपए तक है और जिन्हें अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश मिला है।

इन संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफ़टी), राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (एनआईडी) और अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालय शामिल हैं। केवल प्रथम वर्ष के छात्र ही नई छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, जबकि इसका नवीनीकरण उनके पाठ्यक्रम की पूर्णता तक प्रदर्शन के आधार पर जारी रहेगा।

उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कहा, दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाएं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का आह्वान किया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में संविधान दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय विधान सभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल पर एक 'कॉफी टेबल बुक' का विमोचन किया।

राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसने भारत को एकजुट किया है। उन्होंने कहा, ''अपनी अमृत काल की यात्रा के दौरान हम इसके सिद्धांतों से प्रेरित होकर विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं।'' उपराष्ट्रपति ने कहा, ''एक राष्ट्र के रूप में हमने महिलाओं को सशक्त बनाने से लेकर महिलाओं को विकास का नेतृत्व करने देने तक का बदलाव किया है। रेखा गुप्ता इस बड़े बदलाव का एक उदाहरण हैं।''

राधाकृष्णन ने गुप्ता से दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, न कि टोक्यो, लंदन या अमेरिका के किसी अन्य शहर को। केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दशक में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना रही है। राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि विधायकों को संवाद, बहस और चर्चा के माध्यम से सदन में रचनात्मक योगदान देना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में पहले दिन से मेरा मिशन भेदभाव और अन्याय खत्म करना है : सिन्हा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले दिन से ही उनका मिशन नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना, भेदभाव और अन्याय मिटाना और आतंकवादी परिवेशी तंत्र को खत्म करना रहा है। सिन्हा ने यहां संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई है।

इस अवसर पर, उन्होंने 'संविधान की प्रस्तावना' का वाचन करवाया और संविधान के निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी।

सिन्हा ने कहा, ''67 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, संविधान के प्रावधान 2019 में जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह लागू किए गए (जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द कर दिए और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया), जिससे भेदभाव और अन्याय का शासन समाप्त हुआ।''उपराज्यपाल ने कहा, अब जम्मू कश्मीर बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर द्वारा संविधान में निहित समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है।

संविधान की मूल भावना राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकीकृत करना है : नायब सिंह सैनी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकीकृत करना संविधान की मूल भावना है और उनकी सरकार इसी संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। सैनी ने हरियाणा विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में संविधान दिवस की बधाई देते हुए यह टिप्पणी की।

सैनी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का दिन है क्योंकि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, न्याय और सम्मान प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और जनभागीदारी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा हैं और राज्य की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का आदर्श वाक्य इस भावना को प्रतिबिंबित करता है।

सैनी ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग रहें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि संविधान की गरिमा और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने तथा संवैधानिक मूल्यों के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर सहित कई विधायक और अधिकारी उपस्थित थे।

'डिजिटल उपनिवेशवाद': कैसे एआई कंपनियां साम्राज्यवाद की राह पर चल रही हैं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मेलबर्न। ओपनएआई जैसी बड़ी एआई कंपनियों की नजर में, इंटरनेट पर मौजूद डेटा का भंडार बेहद कीमती है। वे चैटजीपीटी जैसे अपने उत्पादों को प्रशिक्षित करने के लिए फोटो, वीडियो, किताबें, ब्लॉग पोस्ट, एल्बम, पेंटिंग, तस्वीरें और बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं और वे आमतौर पर बिना किसी पारिश्रमिक या रचनाकारों की सहमति के ऐसा करते हैं। दरअसल, ओपनएआई और गूगल का तर्क है कि अमेरिकी कॉपीराइट कानून का एक हिस्सा, जिसे 'उचित उपयोग सिद्धांत' कहा जाता है, इस ''डेटा चोरी'' को वैध ठहराता है। विडंबना यह है कि ओपनएआई ने अन्य एआई दिग्गजों पर भी ''अपनी बौद्धिक संपदा'' का डेटा चुराने का आरोप लगाया है।

दुनिया भर में कई देशों के मूल निवासी (फर्स्ट नेशंस) लोग इन दृश्यों को परिचित अनुभव व समझ के साथ देख रहे हैं। एआई के आगमन से बहुत पहले, लोगों, जमीन और उनके ज्ञान के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था – औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने फायदे के लिए उनका शोषण किया जाता था। एआई के मामले में जो हो रहा है वह एक तरह का 'डिजिटल उपनिवेशवाद' है, जिसमें शक्तिशाली (ज्यादातर पश्चिमी) तकनीकी दिग्गज दूसरों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने और बिना सहमति के डेटा लेने के लिए एल्गोरिदम और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

टेरा नुलियस की कल्पना : टेरा नुलियस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ 'किसी की जमीन नहीं' से होता है। उपनिवेशवादियों द्वारा इसका इस्तेमाल ''कानूनी तौर पर'' जमीन पर दावा करने के लिए किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में टेरा नुलियस की कानूनी कल्पना को 1992 के ऐतिहासिक माबो मामले में पलट दिया गया था। इस मामले में मरे द्वीप समूह के मूल निवासी मेरियाम लोगों के भूमि अधिकारों को मान्यता दी गई। ऐसा करने से, इसने कानूनी दृष्टि से टेरा नुलियस को पलट दिया, जिसके परिणामस्वरूप मूल स्वामित्व अधिनियम 1993 अस्तित्व में आया। हालांकि, जिस तरह से एआई कंपनियां इंटरनेट से अरबों लोगों का डेटा निकाल रही हैं, उसमें हम टेरा नुलियस के विचार के निशान देख सकते हैं। ऐसा लगता है मानो वे मानते हैं कि डेटा किसी का नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश मानते थे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसी का नहीं है।

सहमति के रूप में डिजिटल उपनिवेशवाद : डेटा हमारी जानकारी के बिना ही चुरा लिया जाता है, लेकिन डिजिटल उपनिवेशवाद का एक और भी कपटपूर्ण तरीका है, सामूहिक सहमति के जरिए हमारे डेटा को जबरदस्ती पा लेना।

अभिवादन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ईरोड में रोड़ शो के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए।

पलानीस्वामी 'गद्दार' हैं, भाजपा तमिलनाडु के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईरोड। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी को 'गद्दार' कहा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा को तमिलनाडु के लोगों ने वोट नहीं दिया, इसी वजह से केंद्र ने राज्य के लिए किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार कई परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है, इसलिए विपक्षी दल हताश हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं यह पूछना पसंद नहीं करता कि विधानसभा में विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए ऐसी परियोजनाएं लागू की हैं या नहीं। उन्होंने क्या किया है? केवल विश्वासघात।'' मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''पलानीस्वामी कहते हैं कि वह किसान हैं और अब भी खेती करते हैं। लेकिन वह गद्दार हैं और लगातार विश्वासघात कर रहे हैं। उनके बारे में केवल यही कहा जा सकता है। उन्हें किसान बताना सच्चे किसानों का अपमान करने के समान होगा।''

स्टालिन ने कहा कि अगर पलानीस्वामी सच्चे किसान होते तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य की मांग स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहिए था या नहीं? तमिलनाडु ने केंद्र से धान की खरीद के लिए नमी की स्वीकार्य सीमा को 22 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पलानीस्वामी की विश्वासघात की सूची में कोयंबटूर का नाम भी है क्योंकि केंद्र ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

पुष्पांजलि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बुधवार को तमिल विकास और सूचना विभाग की ओर से इरोड जिले के अराचलूर के ओडानिलाई में स्थित थेरन चिन्नमलाई मणिमंडपम में थेरन चिन्नमलाई तिरुवरुवा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। इस अवसर पर नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू, लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलु, आवास, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के. मुथुसामी, तमिल विकास और सूचना मंत्री एम.पी. स्वामीनाथन, आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री डॉ. एम.ए. मथिवेंथन आदि उफस्थित थे।

भव्य जन्मदिन समारोह टालें, बारिश प्रभावितों की मदद करें: उदयनिधि स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 27 नवंबर को उनके 48वें जन्मदिन पर भव्य समारोह आयोजित करने के बजाय राज्य के बारिश प्रभावित दक्षिणी जिलों में राहत प्रयासों को प्राथमिकता दें।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) युवा शाखा के सचिव उदयनिधि ने कहा कि जन्मदिन खुशी लाता है लेकिन वह भव्य समारोहों के पक्ष में नहीं हैं।

उन्होंने कहा, इसके बजाय मैं संतुष्ट होऊंगा अगर आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो नीतिगत कार्य और जनसेवा का मिश्रण हों। उपमुख्यमंत्री ने पार्टी सदस्यों से गरीबों, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और अन्य वंचित समूहों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ता द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले छोटे आयोजन करेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी।

स्टालिन ने राज्य में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का जिक्र करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को आवेदन फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता करने तथा बूथ स्तर पर काम करने का आग्रह किया। उदयनिधि ने अपने आवास पर आने वाले लोगों से सोने की जरी वाली शॉल, बुके और महंगे उपहार लाने से बचने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके बजाय किताबें, काले-लाल रंग की धोती या महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट करने का सुझाव दिया।

दक्षिण रेलवे में संविधान दिवस मनाया गया

चेन्नई। 26 नवम्बर को चेन्नई में दक्षिण रेलवे के मुख्यालय में दक्षिण रेलवे के अपर महाप्रबंधक विपिन कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इसी प्रकार, सभी छह मंडलों, अर्थात् चेन्नई, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, के मंडल रेल प्रबंधकों और संबंधित मंडल मुख्यालयों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। दक्षिण रेलवे की कार्यशालाओं में भी संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कर्मचारियों और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और बैनर के साथ-साथ प्रस्तावना की प्रतिकृतियाँ भी प्रमुखता से प्रदर्शित की गईं।

संविधान दिवस

चेन्नई। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर, पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली और न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। संविधान दिवस का जश्न चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने और देश और उसके नागरिकों की सेवा करने के अपने कमिटमेंट को फिर से पक्का करने का मौका है।

सीवीआरडीई ने 2025 का संविधान दिवस मनाया

चेन्नई। भारत के संविधान को अपनाने की याद में 26 नवंबर को सीवीआरडीई में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर, सीवीआरडीई के साइंटिस्ट, ऑफिसर, स्टाफ ने सीवीआरडीई के डायरेक्टर की मौजूदगी में प्रस्तावना पढ़कर संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक हालात को अपनाने की कसम खाई। बेहतरीन साइंटिस्ट और सीवीआरडीई के डायरेक्टर जे राजेश कुमार ने मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों और बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान दिवस मनाने का असली मकसद संविधान के चार आदर्शों यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को लागू करना और निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करना है।

धन्यवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में 26 नवम्बर को विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देने के लिए फीनिक्स विकलांग व्यक्ति संघ के महासचिव जयप्रकाश, सचिव मणिकंदन, उपसचिव मुरुगा मुरुगन और नंबियुर पंचायत वार्ड के पार्षद के रूप में राधिका ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

सच्चे संघवाद को कायम रखने और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे: स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को आश्वस्त किया कि वे संविधान में निहित सच्चे संघवाद को कायम रखने और हर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। संविधान दिवस पर अपने संदेश में स्टालिन ने कहा कि भारत सभी लोगों का है, न कि किसी एक संस्कृति या विचारधारा का।

उन्होंने कहा, इस संविधान दिवस पर, हम बाबासाहेब आंबेडकर के दृष्टिकोण को कमजोर करने वाली हर ताकत का विरोध करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। संविधान में निहित सच्चे संघवाद को कायम रखने और हर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे संविधान को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने गणतंत्र की रक्षा उन लोगों से करें जो इसके न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वादे से डरते हैं।

विक्रम सोलर का तमिलनाडु में मॉड्यूल विनिर्माण कारखाना चालू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। सौर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी विक्रम सोलर ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि तमिलनाडु में उसका पांच गीगावाट क्षमता वाला पूरी तरह से स्वचालित वल्लम संयंत्र चालू हो गया है। इसके साथ उसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 9.5 गीगावाट हो गई है।

कंपनी ने बयान में कहा कि 2%,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारखाना अत्याधुनिक टॉपकॉन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अत्याधुनिक वल्लम संयंत्र सालाना पांच गीगावाट की अत्याधुनिक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता जोड़ेगा। इस अगली पीढ़ी के विस्तार के साथ, अब कंपनी की कुल विनिर्माण क्षमता 9.5 गीगावाट प्रति वर्ष हो गई है। विक्रम सोलर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ज्ञानेश चौधरी ने बयान में कहा, इस पांच गीगावाट क्षमता वाले संयंत्र को इसी वर्ष चालू करना एक साहसिक प्रतिबद्धता थी। इसे पूरा करना अगले दशक की मांग के पैमाने, गति और नवोन्मेष के लिए हमारी तत्परता का संकेत है।

उन्होंने कहा, इस उद्योग में 20 से अधिक वर्ष पूरे होने के साथ, यह सुविधा आगे आने वाली चुनौतियों को आकार देने के हमारे इरादे को बताती है। अत्याधुनिक विनिर्माण, स्वचालन-आधारित गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी मंच इस क्षेत्र के लिए नए मानक बनेंगे। वल्लम संयंत्र में विनिर्मित मॉड्यूल पूरे देश में ग्राहकों को आपूर्ति किए जाएंगे। इससे नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को सहायता मिलेगी।

वास्तविक मतदाताओं की रक्षा करें, फर्जी नामों को हटाएं : पलानीस्वामी ने कार्यकर्ताओं से कहा

चेन्नई। अन्नाद्रमुक के महासचिव ई. के. पलानीस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वास्तविक और पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फर्जी या अपात्र नामों को हटाया जाए। अन्नाद्रमुक की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यहां पार्टी कार्यालय से जिला सचिवों और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इकाई के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईआर पर विस्तृत निर्देश जारी किए। पलानीस्वामी ने मंगलवार को बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करते हुए मृत और फर्जी मतदाताओं की तथा मतदाता सूची में दो बार नाम वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें हटाने पर ध्यान केंद्रित करें। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने 2026 में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी और चुनाव संबंधी कार्यों में तेजी लाने को भी कहा।

सबरीमला सोना मामले में झूठे आरोप लगाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज

तिरुवनंतपुरम/भाषा। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सबरीमला सोना चोरी मामले में सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर 'झूठे' आरोप लगाने के लिए एक यूट्यूबर पर मामला दर्ज किया गया है। म्यूजियम पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एस. श्रीजीत की शिकायत के आधार पर मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी के.एम. शाहजहां ने 'यूट्यूब' में अपने चैनल पर झूठी टिप्पणियां की तथा सबरीमला के मुख्य समन्वयक श्रीजीत और पुलिस बल पर मंदिर से सोने की कथित चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया। उसपर धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयानों वाले वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 196(1)(ए) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत दर्ज किया गया है। सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर से सोने की कथित चोरी के मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है। इस घटना की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है और जांच के तहत त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के दो पूर्व अध्यक्षों सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

सबरीमला सोना मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार को दो दिन की एसआईटी हिरासत में भेजा गया

कोल्लम/भाषा। केरल की एक अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और डीटीबी के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर से सोना गायब होने से संबंधित मामले की जांच कर रही एसआईटी की दो दिन की हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि विशेष सतर्कता अदालत ने श्रीकोविल (गर्भगृह) के चौखटों से सोना गायब होने के संबंध में पद्मकुमार से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने के विशेष जांच दल (एसआईटी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बृहस्पतिवार शाम को अदालत में पेश किया जाएगा। पद्मकुमार को पिछले बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। माकपा के पूर्व विधायक पद्मकुमार 2019 में टीडीबी के अध्यक्ष थे।

आईआईटी मद्रास ने बंदरगाहों के लिए देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है और इसे बंदरगाहों में उपयोग में लाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उल्लेखित आवश्यकताओं के आधार पर आईआईटी मद्रास स्थित राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) ने इस प्रणाली को तैयार किया है।

एनटीसीपीडब्ल्यूसी के प्रमुख के. मुरली के अनुसार, यह प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगी तथा आयात पर निर्भरता कम करेगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी प्रणाली से पोत की आवाजाही से संबंधित रणनीतिक डेटा के लीक होने का खतरा नहीं होता। मुरली ने कहा, ''यह प्रणाली आसानी से उन्नत की जा सकती है ताकि संबंधित हितधारकों की लगातार बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जा सके। यह प्रणाली पहले ही केरल में स्थित विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) में लागू कर दी गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में किया था।'' उन्होंने कहा, ''पश्चिमी तट पर स्थित दो अन्य बंदरगाह भी इस प्रणाली को लागू करने के लिए आईआईटी मद्रास से बातचीत कर रहे हैं। स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन का एक प्रमुख लाभ यह है कि सरकार के पास इसके स्रोत कोड, डेटाबेस और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर पूरा रणनीतिक नियंत्रण होता है।''

सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर युवा 'राष्ट्र प्रथम' को रखें सर्वोपरि : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और साहसिक निर्णयों से भारत को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' को सर्वोपरि रखें तथा एक मजबूत, एकजुट तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। शर्मा ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमें दिया है तथा उसी आधार पर देश आगे बढ़ रहा है।

शर्मा ने बुधवार को अमर जवान ज्योति से सरदार150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह यात्रा के तहत आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे देशभर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी के तहत यमुना प्रवाह यात्रा भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के तहत राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों से युवा जयपुर से कमरसद तक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा युवाओं के लिए सरदार पटेल के जीवन, संघर्ष और देशभक्ति को करीब से जानने का अवसर है। साथ ही, युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों और मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा। बारडोली सत्याग्रह में उनकी प्रभावशाली भूमिका के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और सरदार पटेल जेल भी गए। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया।

शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली लेकिन विभाजन का दर्द भी सहना पड़ा। उस समय देश सैकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था। उन्होंने कहा कि देश की 562 रियासतें स्वतंत्र इकाई थी। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और कभी-कभी कठोरता का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक रियासत को भारत में मिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद तथा जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भारत में शामिल कराया। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया और उसे पूरा करके दिखाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। सरदार पटेल का अधूरा सपना प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक आज भारत एक हो रहा है।

सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देते हुए विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में गरीब कल्याण, विकास योजनाओं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा तथा विश्व पटल पर देश का सम्मान बढ़ने जैसे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है तथा दुनिया के सबसे बड़े लीडर के नेतृत्व में देश नई ऊचाईयां छू रहा है।

शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन युवाओं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। युवा पीढ़ी उनके जीवन से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प, एकता तथा सादगी की पांच प्रमुख सीख ले सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरदार150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया। इस दौरान सांसद मदन राठौड़, श्रीमती मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, जितेन्द्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, बालमुकुन्दाचार्य सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

रिश्वत लेते हुए तिलम संघ का महाप्रबंधक गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को कोटा जिले में तिलम संघ के महाप्रबंधक को 30,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एसीबी के अनुसार तिलम संघ कोटा के महाप्रबंधक रमेश चंद्र बैरागी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि बारां जिले में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का आवंटन करने के बदले एक लाख रुपये और एक अन्य काम के लिए उससे 145000 रिश्वत मांगी जा रही है। टीम ने बुधवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की और शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए बैरागी को गिरफ्तार कर लिया।

जयपुर में सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी प्रदर्शनी की शुरुआत

जयपुर। सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी प्रदर्शनी 'ग्लोबल सोलर एक्सपो -राजस्थान 2025' बुधवार को यहां शुरू हुई जिसमें 100 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया। उन्होंने कहा, राजस्थान पहले ही देश का अग्रणी 'सोलर स्टेट' बन चुका है और अब बड़े पैमाने पर भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश आकर्षित कर रहा है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा, प्रगतिशील नीतियों, बड़े सोलर पार्क और अत्याधुनिक ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण राजस्थान आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी 'ग्रीनएनर्जी हब' बनने की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष रोहित गुप्ता भी मौजूद थे। एक बयान के अनुसार 'ईक्यू इंटरनेशनल' और सी2जेड सोलर एंड डीकार्बनाइजेशन मार्केटप्लेस द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक, नीतिनिर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ पहुंचे। प्रदर्शनी में 100 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं।

संविधान और लोकतंत्र का मजबूत रहना देश के लिए बेहद आवश्यक : अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि संविधान और लोकतंत्र का मजबूत रहना देश के लिए बेहद आवश्यक है। गहलोत ने 'संविधान दिवस' पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, संविधान दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर एवं संविधान निर्माण में योगदान देने वाली सभी हस्तियों को नमन। उन्होंने कहा, संविधान हमारी देश की आत्मा है, इसका सम्मान और रक्षा हर भारतीय का धर्म है। आज संवैधानिक मूल्यों व संस्थाओं पर लगातार आघात हो रहे हैं। ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब संविधान बचाओ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।' कांग्रेस नेता ने कहा, मेरी सभी से अपील है कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र का मजबूत रहना देश के लिए बेहद आवश्यक है।

महिला ने डूबती कार से तीन लोगों को बचाया

जयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक महिला ने पानी भरे गहरे गड्ढे में डूब रही कार से तीन लोगों को बचा लिया। घटना मंगलवार सुबह बांसवाड़ा-डूंगरपुर राजमार्ग पर हुई। पुलिस ने बताया कि डूंगरपुर के अध्यापक नाथूलाल यादव अपनी पत्नी और 11 महीने के बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, इस दौरान हीरोता गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर 10 फुट गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। पुलिस ने बताया कि पास में रहने वालीं सुरता (35) ने जब कार को डूबता देखा तो वह गड्ढे में उतर गईं। पुलिस के अनुसार महिला ने एक पड़ोसी और अपनी बेटी आयुषी की मदद से पहले बच्चे को बाहर निकाला और फिर दंपत्ति को बचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कई लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। सुरता ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज सुनी तो अपने घर से बाहर भागीं, जब वह मौके पर पहुंची तो कार लगभग डूब चुकी थी और सिर्फ उसकी छत दिख रही थी। उन्होंने कहा कि वह पानी में उतरीं और शीशा तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाईं।सुरता ने कहा कि उनकी बेटी और एक पड़ोसी भी उसकी मदद के लिए आए, हाथ में चोट लगने के बावजूद पड़ोसी ने कार की खिड़की तोड़ दी। कार में सवार दंपत्ति को मुश्किल से बाहर निकाला गया। जब व्यक्ति को बचाया गया तो वह बेहोश था। पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गई। घायल दंपत्ति और उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजस्थान में कैसे पूरे वर्ष रह सकता है पर्यटन सीजन, बतायेंगे विषय विशेषज्ञ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । प्रवासी राजस्थानी दिवस के पूर्व आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गुरुवार (27 नवम्बर 2025) को जयपुर के क्लार्क्स आमेर में प्रातः 11. 00 बजे पर्यटन प्री समिट का आयोजन होगा। जिसमें राजस्थान को वर्ष भर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और पहचान दिलाने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस प्री- समिट के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्बोधन होगा, वहीं विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री व पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति मंत्री दियाकुमारी होंगी।

उद्घाटन सत्र में केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव सुमन बिल्ला भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के अतरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ का सम्बोधन भी होगा। प्री-समिट में उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न विषय विषेशज्ञ राजस्थान में पर्यटन के विकास और वर्ष भर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में इसकी वैश्विक पहचान बनाने की रणनीति पर अपने सम्बोधन देंगे।

इसके तहत प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता राजीव खंडेलवाल बताएंगे कि कैसे फिल्में राजस्थान को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढावा दे सकती हैं। वहीं ईज माय ट्रिप कम्पनी की अध्यक्ष प्रीति सत्यनारायण राजस्थान को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढावा देने के लिए डिजीटल मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। वहीं लाली होमस्टे की सह निर्माता देवयानी भटनागर राजस्थान में होमस्टे पर घरेलू पर्यटन वृद्धि के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगी। इनके अलावा क्लार्क्स ग्रुप ऑफ होटल्स के एमडी अपूर्व कुमार पर्यटन और निवेश के अवसरों के माध्यम से आर्थिक विकास पर चर्चा करेंगे। यह पर्यटन प्री समिट प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में पर्यटन सेक्टर पर होने जा रहे सेक्टरोल सत्र की नींव तैयार करेगा ताकि उस सत्र में राजस्थान में पर्यटन विकास पर और सार्थक चर्चा हो सके।

योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद को समय से योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने बुधवार को शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक मामलात तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिये।

श्रीनिवास ने विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा उनकी बेहतर तथा समयबद्ध क्रियान्विति के लिए दिशा- निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जीवित प्रमाण पत्र समय से प्राप्त नहीं होने के चलते किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिये। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म और न्यूरो मसक्यूलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों की सहायता के लिए पब्लिक हैल्थ लैक्चर आयोजित किये जाएं। मुख्य सचिव ने पोषण ट्रेकर एप के बारे में भी जानकारी ली और कुपोषण के शिकार बच्चों की उचित देखभाल के लिए बडी मदर्स कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विभाग कहा।

उन्होंने बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना को अभियान चलाकर क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि सहरिया जनजाति परिवारों को दिये जाने वाले राशन किट की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मातृ वंदन और जननी सुरक्षा योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने विभाग द्वारा चलाई जा रही देवनारायण स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, पालनहार योजना तथा विभाग की विभिन्न पेंशन व छात्रवृत्ति योजनाओं योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पेंशन और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल एवं उद्यमिता, रोजगार विभाग संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कुंजी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अवसरों का लाभ उठाते हुए नई गतिविधियां शुरू कर व्यवसाय में वृद्धि करें सहकारी संस्थाएं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) की प्रशासक श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवसाय में वृद्धि के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार भी सहकारी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। सहकारी संस्थाओं को इन अवसरों का लाभ उठाते हुए नई गतिविधियां शुरू कर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में लाभ अर्जन एवं रोजगार सृजन के प्रयास करने चाहिए। श्रीमती राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में आयोजित कॉनफेड की 40वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कॉनफेड को जो भी कार्य दिया, उसे पूरा करने में सभी ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य किया। सभी के समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 में कॉनफेड का कुल टर्नओवर 1,137 करोड़ रुपये का रहा और संस्था ने 26.94 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। कॉनफेड प्रशासक ने विगत वर्ष में बेहतर लाभ अर्जन के लिए सभी को बधाई दी और कॉनफेड के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 हेतु सदस्य संस्थाओं को अधिकतम लाभांश 7.50 प्रतिशत वितरित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वर्ष में भी कॉनफेड भरसक प्रयास कर बेहतर परिणाम हासिल करेगा। श्रीमती राजपाल ने कहा कि अन्न उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है।

अन्न उत्पादक किसानों एवं सहकारी संस्थाओं को इसका लाभ पहुंचाने की मंशा से राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप सहकारी संस्थाओं द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जा रहे हैं।

जानकारी

बीकानेर में बुधवार को बूथ लेवल ऑफिसर छात्रों को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जानकारी देते हुए।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने किया संविधान की प्रस्तावना का वाचन

जयपुर/दक्षिण भारत। 76वें संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को प्रातः 10 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। इस अवसर पर संविधान पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम कार्यक्रम की शुरुआत में सामान्य प्रशासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम एवं कार्मिक विभाग शासन सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

संविधान दिवस पर विशेष बाल संसद एवं संविधान शपथ समारोह का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत बाल संसद एवं संविधान शपथ समारोह का आयोजन सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बाल संसद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, लिंगानुपात और बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया तथा सामाजिक एवं संवैधानिक पहलुओं पर सार्थक चर्चा हुई। बाल संसद के दौरान बच्चों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, उसकी उपयोगिता तथा समाज में न्याय सुलभ करवाने के प्रयासों को रेखांकित किया।

श्रीमती पल्लवी शर्मा ने बाल संसद के दौरान विद्यार्थियों को प्रेरित किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय पाराशर, स्कूल स्टाफ एवं प्राधिकरण के सदस्यों ने संविधान दिवस के बारे में जानकारी दी तथा प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों, अभियानों में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वेदांत पारीक और सुचिर शर्मा को उत्कृष्ट बाल सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विविधता को एकता में जोड़ने वाला है: योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और भारत की विविधता को एकता में जोड़ने वाला है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान की मूल प्रति को लेकर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की समिति जब संविधान सभा के पास गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि संविधान एक दस्तावेज है, जो भारत की विविधता को

एकता में जोड़ने में मार्गदर्शिका के रूप में देश को नेतृत्व प्रदान करेगा। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर लोकभवन में संविधान की प्रस्तावना का सशपथ पाठन कराया। इससे पूर्व अतिथियों ने भारत मां व बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 2015 से पूरा देश प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करता है।

उन्होंने कहा कि 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा ने अलग-अलग कमेटियां बनाई थीं, उसकी 'ड्राॅफ्टिंग कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

योगी ने कहा, '' आज हर संस्था, पंचायत में ऐसे आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का प्रयास हुआ। 2015 में संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हममें से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक है लेकिन स्वतंत्रता की वास्तविक कीमत विस्मृत की जा रही है, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को आंखों से नहीं देखा।''

संविधान देश की प्रगति का मूलभूत आधार है: झारखंड के राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को कहा कि संविधान देश की प्रगति का मूलभूत आधार है। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर लोगों से अपील की कि वे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को अपनाकर देश की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लोगों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा, ''हमारा संविधान न सिर्फ़ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा है, बल्कि देश की प्रगति का मूलभूत आधार भी है।'' उन्होंने कहा, ''आइए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को अपनाकर देश की तरक्की में योगदान दें।''

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर समेत हमारे महान संविधान निर्माताओं को शत-शत नमन। देश का संविधान हमें समानता, समता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर एकजुट करता है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ग्रन्थ है - एक प्रगतिशील, समावेशी और न्यायपूर्ण देश की आधारशिला है।'' उन्होंने कहा, ''आइए, इस दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों को आत्मसात कर हर नागरिक तक विकास, सम्मान और अधिकार की पहुंच सुनिश्चित हो। संविधान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार।''

संविधान दिवस 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की याद में हर साल इस दिन मनाया जाता है।

कोलकाता विधि कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामला: पीड़िता के पिता को मिली मुकदमा वापसी के लिए धमकी

कोलकाता/भाषा। कस्बा विधि कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि दोपहिया वाहन पर सवार अज्ञात लोगों ने उन्हें धमकी दी और मामला वापस लेने को कहा। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बरुईपुर थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिसकर्मी ने कहा, हमें शिकायत मिल गई है और मामले की जांच कर रही अभियोजन टीम को सूचित कर दिया गया है। पीड़िता के पिता ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह उन लोगों की पहचान नहीं कर सकते जिन्होंने कथित तौर पर धमकी दी है।

'साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज' की प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 जून की शाम को एक पूर्व छात्र और दो वरिष्ठ छात्रों ने संस्थान के अंदर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अपराध की रिपोर्ट दो महीने बाद दर्ज की गई, जिसके बाद जांच अधिकारियों ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। ये सभी फिलहाल जमानत पर हैं और मुकदमे की सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली है।

ओडिशा ने विदेश में अध्ययन के लिए एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सरकार ने बुधवार को 'विदेश शिक्षा वृत्ति' योजना की शुरुआत की, जो विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने की आकांक्षा रखने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मेधावी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत की, जिसे 202526 शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत एससी और एसटी वर्ग के वे छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए या उससे कम है।

आवेदकों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 में शामिल विदेशी विश्वविद्यालयों या संस्थानों में पीजी या पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश मिला होना चाहिए।

सूरज ने कहा कि आवेदन वर्ष में दो बार जुलाईअगस्त और दिसंबरजनवरी के दौरान आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हर साल 50 छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया जाएगा। इनमें से इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा से 10 (चार पीजी और छह पीएचडी) , मेडिकल , कृषि, वास्तुकला और अन्य तकनीकी धाराओं से से 10 (चार पीजी और छह पीएचडी) और 30 (10 पीजी और 20 पीएचडी) उच्च शिक्षा से होंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयनित छात्र को अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए की वृति प्रदान की जाएगी।

योजना की शुरुआत के साथ ही विभाग ने पुनर्वास सहायता के तहत सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में समूह सी और डी के 34 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मंत्री द्वारा प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के दौरान ओडिशा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (ओएसएचइसी) को राज्य भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक प्रदर्शन ऑडिट (एपीए) करने का अधिकार भी मिला। सूरज ने कहा कि इससे शैक्षणिक मानकों का मूल्यांकन और सुधार संभव होगा तथा ओडिशा ऐसा तंत्र अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

असम से 32,000 विदेशियों में से 1,416 को निर्वासित किया गया: हिमंत विश्व शर्मा

गुवाहाटी/भाषा। असम में 2021 में हिमंत विश्व शर्मा की सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से 32,000 से अधिक विदेशियों का पता लगाया गया और उनमें से 1,416 को निर्वासित किया गया है। विधानसभा को बुधवार को यह जानकारी दी गई।

कांग्रेस विधायक अब्दुर रहीम अहमद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में असम समझौता कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि 2021 से इस वर्ष 31 अक्टूबर तक असम में अवैध रूप से रह रहे कुल 32,207 विदेशियों का पता लगाया गया। उन्होंने कहा, इनमें से 1,416 को असम से निर्वासित किया जा चुका है। बोरा ने वर्षवार ब्योरा देते हुए बताया कि 2021 में 6,304, 2022 में 8,790, 2023 में 6,703, 2024 में 6,120 और 2025 में 4,290 विदेशियों का पता लगाया गया।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, केवल विदेशी न्यायाधिकरण ही असम में किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर सकता है, और यदि फैसला अनुकूल नहीं होता है तो उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है।

असम समझौते के अनुसार, 25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम आने वाले सभी विदेशियों के नाम का पता लगाया जाएगा तथा मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे एवं उन्हें निर्वासित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

मणिपुर के चुराचांदपुर में 40 किलो विस्फोटक वाला रॉकेट बरामद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से लगभग 40 किलोग्राम विस्फोटक वाला लंबी दूरी का एक इंप्रोवाइज्ड रॉकेट बरामद किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को गेलमोल गांव में सुरक्षा बलों के अभियान में यह रॉकेट बरामद हुआ जिसके साथ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टैंड और एक बैटरी भी बरामद की गई है। उसने बताया कि एक अन्य अभियान में कांगपोकपी जिले में बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, बरामद सामग्री में तीन प्रकार की सात राइफल, एक देसी मोर्टार, दो हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और एक रेडियो सेट शामिल हैं। यह जब्ती सॉन्गलंग गांव के पास से की गई।

इसके अलावा, चुराचांदपुर जिले के गेलबुंग जंगल से भी कई हथियार बरामद किए गए। इनमें एक सीएमजी कार्बाइन, एक .303 राइफल, दो पिस्तौल, नौ बोल्ट-एक्शन राइफल, एक देसी एसएसबीएल, एक देसी ग्रेनेड, तीन प्लास्टिक विस्फोटक और दो हैंडसेट शामिल हैं।

एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी लागू करने की है : ममता ने लगाया आरोप

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पीछे असली मंशा पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने और आम आदमी में डर पैदा करने की है।

संविधान दिवस के अवसर पर रेड रोड स्थित बी. आर. आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद बनर्जी ने कहा कि मौलिक अधिकारों पर खतरा है। उन्होंने अपने हाथ में संविधान की प्रति लिए हुए कहा, ''मैं दुख के साथ यह देख रही हूं कि लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, उनके धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। गंदी भाषा का इस्तेमाल करके हमले किए जा रहे हैं, और किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, यहां तक कि दलितों, अल्पसंख्यकों या आम हिंदू मतदाताओं को भी नहीं। इसके पीछे असली मंशा एनआरसी लागू करने की है। हम स्तब्ध और दुखी हैं। इसलिए मैं आज यहां भारत के लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेती हूं।'' बनर्जी ने आरोप लगाया कि वर्षों तक इस देश की मिट्टी को सिंचित करने वालों से भारत में उनके रहने के अधिकार को साबित करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, ''नागरिकता के अधिकार के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है।'' इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता ''खतरे में हो'' और संघवाद को ''ध्वस्त किया जा रहा हो'', तो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। बनर्जी ने कहा कि संविधान राष्ट्र की रीढ़ है, जो भारत की संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की विविधता को कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोता है। उन्होंने कहा, ''आज, संविधान दिवस पर मैं हमारे महान संविधान और भारत में हमें जोड़ने वाले महान दस्तावेज के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मैं आज संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं विशेष रूप से इसके प्रमुख वास्तुकार डॉ. बी.आर. आंबेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।''

'मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है, लेकिन मेरी सफलताओं को मत भूलना'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। आलोचनाओं से घिरे भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बुधवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट शृंखला में मिली करारी हार के बाद उनके भविष्य पर फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को करना है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में टीम ने कितनी सफलता हासिल की है।

गंभीर बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद बोल रहे थे, जिससे मेहमान टीम ने शृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। मैंने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में भी कहा था जब मैं मुख्य कोच बना था । भारतीय क्रिकेट अहम है, मैं नहीं । आज भी मैं वही बात कह रहा हूं ।'' उन्होंने कहा,'' लोग भूल जाते हैं लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसने युवा टीम के साथ इंग्लैंड में आपको अनुकूल परिणाम दिलाए । मुझे यकीन है कि आप जल्दी ही भूल जाओगे क्योंकि अधिकांश लोग न्यूजीलैंड (पिछले महीने भारत में 0 . 3 से मिली हार) के बारे में बात करते रहते हैं । मैने चैम्पियंस ट्रॉफी और एशिया कप में भी जीत दिलाई है ।''गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से मिली हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ''दोष सभी का है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है। हमें बेहतर खेल दिखाना होगा। पहली पारी में एक समय स्कोर एक विकेट पर 95 रन था जो सात विकेट पर 122 रन हो गया। यह स्वीकार्य नहीं है।आप किसी एक व्यक्ति या किसी ख़ास शॉट को दोष नहीं दे सकते। दोष सबका है। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा। हमें बेहतर खेलना होगा । एक विकेट पर 95 रन से सात विकेट पर 122 रन स्वीकार्य नहीं है।'' गंभीर के कोच रहते भारत ने 18 टेस्ट मैचों में से 10 में हार का सामना किया है, जिसमें पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हार भी शामिल है।

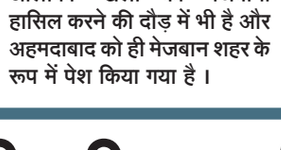

भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली

नई दिल्ली/भाषा। भारत बीस साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों की आमसभा की बैठक में अहमदाबाद को मेजबान के तौर पर औपचारिक मंजूरी मिल गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (खेल) कुणाल, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य लोगों ने किया ।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉ डोनाल्ड रुकारे ने कहा, ''यह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। भारत व्यापकता, युवा शक्ति, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति, अपार खेल-जुनून और प्रासंगिकता लेकर आता है। हम राष्ट्रमंडल खेलों के अगले शतक की शुरुआत मजबूत स्थिति में कर रहे हैं। '' राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने सौ साल भी पूरे कर रहे हैं लिहाजा यह संस्करण विशेष रहने वाला है । भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दौड़ में भी है और अहमदाबाद को ही मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है ।

एसआईआर के जरिये लोकतंत्र को 'एकतंत्र' में बदलने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है : दिग्विजय सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग पर बुधवार को हमला बोला और आरोप लगाया कि एसआईआर की 'पूरी तरह दोषपूर्ण प्रक्रिया' के जरिये लोकतंत्र को 'एकतंत्र' में बदलने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संविधान दिवस पर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही।

सिंह ने शहर के गीता भवन चौराहे पर संविधान निर्माता डॉ. बीआर आम्बेडकर के प्रतिमा स्थल के पास आयोजित सभा में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया 'पूरी तरह दोषपूर्ण' है। उन्होंने एसआईआर पर निशाना साधते हुए कहा,''भारत के संविधान को लोकतंत्र से एकतंत्र में बदलने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। हमारी मतदाता सूची से छेड़खानी की जा रही है। यह छेड़छाड़ केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। आपकी नागरिकता पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।''

सिंह ने कहा,''देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। हमें निर्णय करना है कि देश में एकतंत्र होना चाहिए या लोकतंत्र?'' उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के उदाहरण देते हुए कहा कि 'एकतंत्र' में केवल एक व्यक्ति का राज चलता है और आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि देश में 2003 तक जो एसआईआर होता था, उसमें हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की होती थी, लेकिन एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया के तहत खुद नागरिकों से उनके मतदाता होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के तहत करीब 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची के मसौदे से हटाए जाने पर सवाल उठाए और कहा,क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं थे? अक्सर घुसपैठियों की बात की जाती है, लेकिन क्या उन्हें (निर्वाचन आयोग को) बिहार में एक भी घुसपैठिया मिला?

भारत की सबसे बड़ी हार, द. अफ्रीका ने 25 साल बाद फिर किया क्लीन स्वीप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने कौशल और दृढ़ संकल्प की कमी वाले भारतीय बल्लेबाजों को फिर से दिन में तारे दिखाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 408 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करके दो मैच की शृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उसकी सबसे बड़ी हार है। यह तीसरा अवसर है जबकि किसी टीम ने भारत का उसकी धरती पर सूपड़ा साफ किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2000 में 2-0 से जबकि पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से शृंखला जीती थी। इस पराजय से भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है।

भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में, भारत अब तक घरेलू मैदान पर न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टेस्ट हार चुका है। पिछले 66 वर्षों में यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम सात महीनों के अंतराल में पांच टेस्ट हार गई।

भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए। उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए। हार्मर ने पिच मुझे मिल रहे उछाल और टर्न का पूरा फायदा उठाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए।

एडेन मार्क्रम ने नौ कैच लेकर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के अजिंक्य रहाणे के 2015 में लिए गए आठ कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। भारत ने सुबह दो विकेट पर 27 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई जिसके बाद हार्मर ने अपने टर्न और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने पहले सत्र में नाइटवॉचमैन कुलदीप यादव (05), ध्रुव जुरेल (02) और कप्तान ऋषभ पंत (13) को पवेलियन की राह दिखाई। बारसापारा की पिच हाल के समय में उपलब्ध कराई गई सर्वश्रेष्ठ भारतीय पिचों में से एक थी, जिसमें उचित तकनीक और अभ्यास से बल्लेबाज रन बनाने में सक्षम थे। इस पिच पर अपनी लेंथ को जानने वाले तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और चालाक स्पिनरों ने दबदबा बनाया। हार्मर ने सुबह के सत्र में आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कुलदीप के डिफेंस में सेंध लगाई और फिर इसी ओवर में जुरेल को भी पवेलियन की राह दिखाई। जुरेल ने पहली स्लिप में खड़े मार्क्रम को कैच का अभ्यास कराया। पंत ने केशव महाराज पर छक्का लगाया लेकिन हार्मर की उछाल लेती एक गेंद उनके बल्ले को चूमती हुई स्लिप में मार्क्रम के सुरक्षित हाथों में चली गई।

आप क्रिकेट को हल्के में नहीं ले सकते, हमें बेहतर बनने की जरूरत है: पंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने बुधवार को स्वीकार किया कि भारत को टेस्ट टीम के रूप में बेहतर बनने की जरूरत है और कहा कि सिर्फ घरेलू हालात में खेलने से नतीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका ने यहां दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर शृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

पंत ने मैच के बाद कहा, ''यह थोड़ा निराशाजनक है। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हमें विरोधी टीम को श्रेय देना होगा। उन्होंने पूरी शृंखला में दबदबा बनाया लेकिन घरेलू धरती पर खेलने से आप क्रिकेट को हल्के से नहीं ले सकते हैं।'' पंत ने कहा कि भारत को इस शृंखला से सीख लेनी होगी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा, ''हमें इससे सीख लेकर एक टीम के रूप में आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी मानसिकता स्पष्ट रखनी होगी। हमें इससे सीखना होगा और बेहतर बनना होगा।''

इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने पूरी शृंखला में बेहतर क्रिकेट खेली।

सुविचार

जैसे एक बछड़ा हजार गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने करता को ढूढ ही लेता है..!!!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

एसआईआर से समस्या क्यों?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान दिवस के अवसर पर एसआईआर के बारे में जो बयान दिया, उसमें सच्चाई कम और भ्रम ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ममता और कई नेताओं को एसआईआर से समस्या क्यों है? यह प्रक्रिया कोई पहली बार तो नहीं हो रही है। इसके तहत मतदाता सूची में मौजूद खामियों को दूर किया जा रहा है। अब जबकि एसआईआर हो रहा है तो कुछ नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अगर एसआईआर समयानुसार नहीं होता तो भी कुछ नेता इसे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करार देते। ममता बनर्जी एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर प्रचारित कर रही हैं, जबकि दोनों प्रक्रियाएं पूरी तरह अलग हैं। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता का निर्धारण नहीं कर रहा है। वह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। अगर इस दौरान सूची में अपात्र लोग पाए जाएंगे तो क्या उनका नाम नहीं काटना चाहिए? ये नेतागण लोकतंत्र का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। मतदाता सूची से अपात्र लोगों के नाम काटने और पात्र लोगों के नाम जोड़ने से लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? इस सूची में अपात्र लोगों के नाम क्यों होने चाहिएं? क्या देश ऐसे चलेगा कि कोई भी व्यक्ति यहां आकर मतदाता बन जाए? ममता बनर्जी एक बार बांग्लादेश सीमा से आ रहे वीडियो देखें। सिर पर गठरी और हाथ में थैला लेकर जा रहे ये लोग कौन हैं? अचानक इनके झुंड बांग्लादेश का रुख क्यों करने लगे? क्या ढाका में इन सबकी लॉटरी लग गई है?

एसआईआर के बारे में सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, जो पकड़े जाने के डर से भाग रहे हैं। कुछ नेताओं को इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका वोटबैंक हाथ से निकलता जा रहा है। अगर पूरे देश में भलीभांति एसआईआर हो जाए तो भविष्य में एनआरसी की ज्यादा जरूरत ही न पड़े। अभी प. बंगाल से घुसपैठिए निकल रहे हैं। फिर, देश के कोने-कोने से घुसपैठिए निकल भागेंगे। सोशल मीडिया पर प. बंगाल के ऐसे वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कुछ लोग एसआईआर के बारे में अजीब कुतर्क दे रहे हैं। वे संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में इस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे नागरिकों पर मुसीबतों का कोई पहाड़ टूट पड़ा! जो भारतीय नागरिक है, उसे न तो इन कुतर्कों को बढ़ावा देना चाहिए और न ही इन पर विश्वास करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए जो दस्तावेज मांगे हैं, वे हर भारतीय के घर में आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग यह कहकर प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है! क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? कोई व्यक्ति / परिवार कई वर्षों से भारत में रह रहा है, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसे नहीं पहचानते, तो वह कौन है? इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है कि दस्तावेज थे, लेकिन बाढ़ में बह गए। आज ज्यादातर दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उनकी प्रतिलिपियां डाउनलोड की जा सकती हैं, मंगवाई जा सकती हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इस समय सरकार किसी योजना की घोषणा कर आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दे तो लोग कागज ही कागज ले आएंगे। जो बांग्लादेशी स्वदेश लौट रहे हैं, उनके लिए यह कहकर पक्ष में माहौल बनाना अनुचित है कि 'गरीब लोगों को निकाला जा रहा है।' क्या गरीब लोग भारत में कम हैं? बांग्लादेश के गरीबों को रोजगार देना भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब देश अलग हैं तो उनकी सरकारों की जिम्मेदारियां भी अलग हैं। बांग्लादेशियों को स्वदेश जाना ही चाहिए और वहां मो. यूनुस से रोजगार मांगना चाहिए। एसआईआर किसी सूरत में नहीं रुकना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

आज ही के दिन वर्ष 1949 में हमारे संविधान मनीषियों के अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से हमें ऐसा महान संविधान मिला, जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व तथा हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। हमारा संविधान हमारा गौरव है।

-ओम बिरला

आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में स्पेशल ओलिंपिक भारत द्वारा साउथ वेस्ट कमांड के सहयोग से आयोजित स्टेट गेम्स एथलेटिक्स 2025 का शुभारंभ कर सभी ऊर्जावान एथलीट्स का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की।

-दिया कुमारी

संविधान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह भारत के उज्ज्वल सपनों की दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। आइए, आज प्रण करें कि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करेंगे।

-नरेन्द्र मोदी

प्रेरक प्रसंग

अनमोल भक्ति

आचार्य विनोबा भावे रेलगाड़ी से वर्धा जा रहे थे। उसी ट्रेन के डिब्बे में एक वृद्ध फ़कीर भी चढ़ा। फ़कीर ने भक्ति भाव से एक गीत गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज़ और गीतों के भावों को सुनकर विनोबा जी भावविभोर हो उठे। डिब्बे में अन्य यात्री भी फ़कीर के गायन के जादू से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। उसी डिब्बे में एक धनाढ्य जमींदार भी बैठा था। उसने अपने जेब से पांच रुपये का नोट निकाला और फ़कीर से बोला, 'एक-एक पैसा इकट्ठा करने से भला क्या होगा? मैं रुपये देता हूं, बस शर्त यह है कि तुम भजन की जगह फिल्मी गीत गाओ।' फ़कीर ने जवाब दिया, 'मैंने नियम बना रखा है कि परमात्मा के अलावा किसी की भी वाणी से प्रशंसा नहीं करूंगा।' जमींदार ने फिर सौ रुपये का नोट निकाला और कहा, 'नियम-वियम को ताक पर रखो, यह सौ रुपये लो और फिल्मी गीत गाओ।' फ़कीर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, 'आप एक लाख रुपये देंगे तब भी मैं भगवान की स्तुति के अलावा किसी और के गीत नहीं गाऊंगा।' फ़कीर के इन शब्दों को सुनकर आचार्य विनोबा भावे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उठकर उसे गले से लगा लिया और बोले, 'आज पता चला है कि सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई की परंपरा के सच्चे भक्त अभी भी इस पृथ्वी पर हैं।

सामयिक

आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की अनिवार्य पुकार

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'

मोबाइल : 9955818270

राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी संप्रभु देश की रीढ़ होती है। यह केवल सीमा पर तैनात जवानों की बहादुरी का प्रश्न नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का भी परिणाम है, जो किसी राष्ट्र को मजबूत रक्षा तैयारियों का आधार प्रदान करती हैं। भारत में पिछले एक दशक में जिस तेजी से आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वह न केवल बदलते वैश्विक परिदृश्य का अनिवार्य परिणाम है, बल्कि उन चुनौतियों का उत्तर भी है जो नई तकनीकों, आधुनिक युद्धक रणनीतियों और जटिल सुरक्षा परिवेश के कारण उभर रही हैं। इसी संदर्भ में तेजस लड़ाकू विमान के विकास, उसके परीक्षण, उसके साथ घटित घटना और उससे निकले सबक हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि आत्मनिर्भरता का मार्ग कितना जटिल और जरूरी है। भारतीय रक्षा तकनीकी विकास के इतिहास में तेजस एक ऐसा अध्याय है, जिसने देश को वैश्विक मंच पर नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा किया। 2007 में इसके निर्माण की शुरुआत के साथ ही भारत ने यह संदेश दिया कि वह अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह देश में विकसित करने की क्षमता रखता है। जुलाई 2016 में जब भारतीय वायुसेना ने तेजस के पहले स्क्वॉड्रन का गठन किया, तो यह केवल एक विमान की उड़ान नहीं थी, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और विविध रक्षा अनुसंधान संस्थानों की सामूहिक क्षमता का उद्घोष था। यह वह क्षण था जहां अनुभव से अधिक संकल्प का महत्व दिखाई देता है, एक ऐसा राष्ट्र जो दशकों तक विदेशी रक्षा तकनीक पर निर्भर रहा, अब स्वयं के बलबूते पर आधुनिक विमान निर्माण में अग्रसर था। लेकिन विकास की इस यात्रा में चुनौतियाँ स्वाभाविक थीं। हाल ही में तेजस के एक विमान ने तकनीकी कारणों से आपातकालीन लैंडिंग की, जिसने देशभर में चर्चा और चिंता दोनों को जन्म दिया। यह घटना अपने आप में कोई असाधारण दुर्घटना नहीं थी, लेकिन उसने रक्षा प्रणाली में तकनीकी परिशुद्धता, निगरानी और उच्चतम मानकों की आवश्यकता को पुनः रेखांकित किया। हर उन्नत देश में, चाहे वह अमेरिका हो या रूस, ऐसे तकनीकी बाधाओं के उदाहरण मिलते हैं। किंतु भारत के संदर्भ में यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि यह समय उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ देश आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को न केवल लक्ष्य, बल्कि प्राथमिकता का विषय बना चुका है।

तेजस की तकनीकी संरचना की बात करें तो यह विमान अत्याधुनिक डिजाइन, हल्के कॉम्पोज़िट ढांचे और उच्च सुरक्षा प्रणालियों का बेहतरीन संगम है। 'कार्बन फाइबर' से निर्मित इसके ढांचे ने न केवल विमान का वजन कम किया, बल्कि उड़ान के दौरान इसकी स्थिरता और मजबूती को भी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया। इसकी फ्लाई-बाय-वायर' प्रणाली, उन्नत एवियोनिक्स और चौथी पीढ़ी के मानकों पर आधारित क्षमताएँ इसे दुनिया के उन चुनिंदा विमानों की श्रेणी में शामिल करती हैं जो गति, तकनीक और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखते हैं। वर्षों के परीक्षणों और संशोधनों के बाद तेजस एक भरोसेमंद और कुशल लड़ाकू विमान बन चुका है, जिसे भारतीय वायुसेना लगातार उन्नत संस्करणों में शामिल कर रही है। किन्तु हर तकनीकी उपलब्धि की तरह तेजस के विकास में भी समस्याएँ आईं, कभी इंजन के प्रदर्शन को लेकर, कभी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को लेकर और कभी उड़ान परीक्षणों के दौरान आवश्यक संतुलन को लेकर। इन समस्याओं को हल करने में वैज्ञानिकों ने अनगिनत दिन-रात खर्च किए। और यही वह श्रम है जो आत्मनिर्भरता को मूल्यवान बनाता है। यदि किसी राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसे ऐसे संघर्षों से गुजरना ही पड़ता है। किसी विमान का एक पुर्जा भी यदि बाहर से मंगाना पड़े, तो सुरक्षा की एक छोटी-सी खिड़की खुल जाती है, जिसे आधुनिक युद्धक परिदृश्य में कोई भी देश वहन नहीं कर सकता।

भारत की रक्षा नीति में इन दिनों दो स्पष्ट लक्ष्य दिखाई देते हैं- पहला, पूरी तरह स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और दूसरा, रक्षा निर्यात को नए स्तर पर ले जाना। 2013- 14 में जहां भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपये था, वहीं 2024- 25 में यह 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि भारतीय तकनीक पर वैश्विक विश्वास का संकेत है। यह विश्वास एक दिन में नहीं बनता; यह वर्षों की लगातार मेहनत, प्रयोगों, असफलताओं और सुधारों की देन है। तेजस की हालिया तकनीकी समस्या ने एक बार फिर यह चेतावनी दी है कि आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखना भी है। रक्षा उपकरण कोई सामान्य औद्योगिक वस्तु नहीं होते। उनका एक-एक पुर्जा सैनिकों की जान, राष्ट्र की सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। इसलिए उनकी गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता संभव नहीं। तेजस के किसी भी तकनीकी परीक्षण में आई त्रुटि केवल एक तकनीकी मामला नहीं, बल्कि एक सबक है कि सुधार की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए और आत्मनिर्भरता का मार्ग केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि उत्कृष्टता का मार्ग है। तेजस की घटना यह भी बताती है कि तकनीक की दुनिया बदलते समय के साथ चुनौतीपूर्ण होती जाती है। जैसे-जैसे युद्धक तकनीक विकसित होती है, वैसे-वैसे उसके मानक भी कठोर होते जाते हैं। आज का विमान केवल तेज या हल्का होना पर्याप्त नहीं, उसे साइबर-सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, उच्च-स्तरीय सेंसर तकनीक और नेटवर्क-आधारित युद्ध प्रणाली के अनुरूप भी होना चाहिए। इसीलिए तेजस के वर्तमान संस्करण के साथ-साथ भारतीय वैज्ञानिक तेजस मार्क- 2' और एएमसीए' जैसे अत्याधुनिक विमानों पर काम कर रहे हैं, जिनसे आने वाले समय में भारत की वायु-शक्ति अधिक स्वदेशी, अधिक सक्षम और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत होने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- विश्वास। देश का विश्वास अपने वैज्ञानिकों पर, वैज्ञानिकों का विश्वास अपनी खोजों पर और रक्षा बलों का विश्वास स्वदेशी प्रणालियों पर। तेजस की घटना ने इस विश्वास को झकझोरा नहीं, बल्कि मजबूत किया है क्योंकि यह घटना तकनीकी समस्या के बाद भी विमान को सुरक्षित उतारने और पायलट की जान बचाने की क्षमता को प्रमाणित करती है। ऐसी घटनाएँ यह भी याद दिलाती हैं कि आत्मनिर्भरता का मार्ग शुरुआत में कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में यही मार्ग किसी भी देश को मजबूत, स्वतंत्र और सुरक्षित बनाता है।

इस तरह से तेजस की हालिया तकनीकी बाधा एक घटना भर नहीं, बल्कि एक संदेश है, हमें अपने रक्षा निर्माण की नींव को और मजबूत बनाना होगा, अनुसंधान को और गहरा करना होगा, निगरानी की प्रणालियों को अधिक संवेदनशील बनाना होगा और गुणवत्ता के मानकों को अटल दृढ़ता के साथ लागू करना होगा। जब तक हम रक्षा उपकरणों की प्रत्येक प्रक्रिया को अपने नियंत्रित और सक्षम हाथों में नहीं लेते, तब तक आत्मनिर्भरता का स्वप्न अधूरा रहेगा। भारत आज सही दिशा में अग्रसर है। तेजस जैसे प्रयास, उनकी चुनौतियाँ और उनसे निकले सीखें इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यदि राष्ट्र अपनी तकनीकी क्षमता को उत्कृष्टता के स्तर तक ले जाने का संकल्प रखते हुए आगे बढ़ता रहा, तो न केवल देश की वायु-शक्ति अधिक सुरक्षित बनेगी, बल्कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे विश्वसनीय रक्षा उत्पादकों में भी शामिल होगा। यही वह रास्ता है, जिस पर चलकर हम एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और आधुनिक रक्षा प्रणाली वाले भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ हर उड़ान आत्मविश्वास की हो, हर तकनीक स्वदेशी गर्व का प्रतीक हो, और हर सबक हमें और अधिक सक्षम तथा सजग बनाता हो।

नजरिया

आक्रामक साजिशों के बीच संविधान की असल ताकत

संजय सक्सेना

मोबाइल : 8299050585

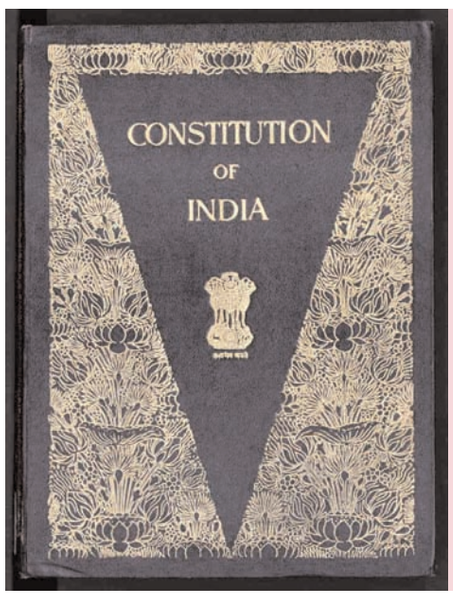

संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं।

26 नवम्बर केवल एक तारीख नहीं, यह तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेज़ी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही। आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संवैधानिक अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्पुष्टि होती है। राष्ट्रपति जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर ज़ोर देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है।

अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मज़बूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज़ नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई। यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की देन था और आज भी इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मज़बूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला। 44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मज़बूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के ज़रिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाज़े पर लोकतंत्र की आवाजाही बढ़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली।अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की व्याख्या केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही। इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमज़ोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में आख़िरी फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने वोट से ज़िंदा रखता है।

संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही संविधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है। आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर गूंजता है, तब भी संविधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेंगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बासी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो संविधान किसी भी तानाशाही इरादे को मात दे सकता है। इसी चेतना को ज़िंदा रखना ही संविधान दिवस का असली उद्देश्य है, और यही वजह है कि इस दिन की राजनीति जितनी गरम होगी, जनता के लिए संविधान की रक्षा की ज़िम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

एआई की मदद से पाकिस्तानी लड़की 17 वर्ष बाद मिली अपने परिवार से

कराची/भाषा

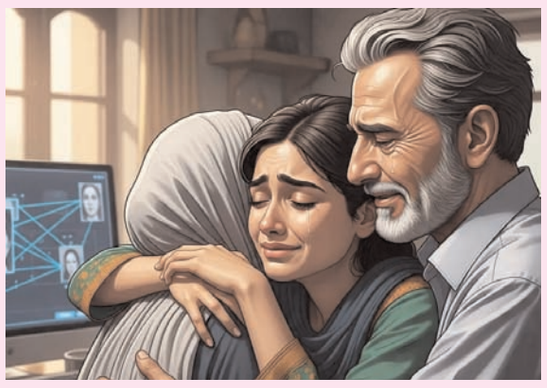

पाकिस्तान में एक 'लापता लड़की' को उसके परिवार से 17 वर्ष बाद मिला दिया गया और इस काम को अंजाम देने में कृत्रिम मेधा और चेहरे की पहचान करने वाले एक सॉफ्टवेयर ने बड़ी भूमिका निभायी। किरण वर्ष 2008 में इस्लामाबाद स्थित अपने मोहल्ले में आइसक्रीम खरीदने के लिए घर से निकली थीं। इस दौरान वह रास्ता भटक गईं और अपना घर नहीं ढूंढ पायी। किरण अब 27 साल की हैं, उन्होंने बताया, मैं खोई हुई थी और रो रही थी। मुझे याद है कि एक दयालु महिला मुझे इस्लामाबाद के ईधी सेंटर ले गई थी क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। कुछ दिनों बाद, दिवंगत अब्दुल सत्तार ईधी की पत्नी बिलकिस ईधी (जिन्होंने 'ईधी फाउंडेशन' नामक एनजीओ की स्थापना की थी) उन्हें कराची ले गईं। तब से, किरण कराची के अब्दुल सत्तार ईधी आश्रय गृह में बिलकिस की देखरेख में पली-बढ़ी। फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष फैसल ईधी की पत्नी सबा फैसल ईधी ने बताया कि किरण के माता-पिता का पता लगाने के लिए वह बार इस्लामाबाद गयी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस साल की शुरुआत में, फाउंडेशन ने पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नबील अहमद से संपर्क किया। यह पहल 2018 में वहां की प्रांतीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सबा ने कहा, हमने उन्हें किरण की नवीनतम तस्वीरें और उनके बचपन और आस-पड़ोस के बारे में जो भी थोड़ी-बहुत जानकारी वह दे सकती थीं, वह सब उपलब्ध कराई। नबील ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने इस्लामाबाद में एक लापता लड़की की पुलिस रिपोर्ट का पता लगाया और नवीनतम एआई तकनीक, चेहरे की पहचान और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लड़की के परिवार का पता लगाने में कामयाब रहे।

इसके तुरंत बाद, पेशे से दर्जी अब्दुल मजीद अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कराची पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने किरण को सालों तक ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। हमने कुछ अखबारों में उसकी तस्वीर भी छपवाई, लेकिन कोई भी किरण को नहीं ढूंढ पाया। किरण ईधी आश्रय गृह की पांचवीं लड़की है, जिसके परिवार का पता लगा लिया गया है, क्योंकि फाउंडेशन अब पूरे पाकिस्तान में पुलिस और सुरक्षित शहर परियोजनाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है।

पाकिस्तान 1947 से भारत के खिलाफ आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है : रिपोर्ट

नयी दिल्ली/भाषा

मुंबई आतंकवादी हमले की 17वीं बरसी के अवसर पर बुधवार को विचारक संस्था 'नैटस्ट्रैट' द्वारा 1947 से 2025 के बीच सीमा पार से किए गए प्रमुख आतंकवादी हमलों का विवरण देने वाला एक दस्तावेज जारी किया गया। सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर शोध के लिए एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्था 'नैटस्ट्रैट' द्वारा संकलित रिपोर्ट में कहा गया है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के इतिहास को बार-बार बताया जाना चाहिए। वर्ष 1947 से शुरू होकर वर्तमान तक के रिकॉर्ड पाकिस्तान की सेना और खुफिया इकाई 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आईएसआई) द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने की एक सतत रणनीति का संकेत देते हैं। 'भारत पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमले का कालक्रम 1947-2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है - 1947-71 आधारभूत संघर्षों के युग के रूप में; 1972-89 छद्म युद्ध के उदय के रूप में; 1990-2000 उग्र और शहरी हमलों के रूप में; 2001-09 राष्ट्रीय प्रतीकों को निशाना बनाने के रूप में और 2010-25 आतंकवाद के बदलते स्वरूप और कठोर प्रतिक्रिया के रूप में।

धरना

কोलकाता में बुधवार को बूथ लेवल ऑफिसर और उनके साथी चुनाव आयोग ऑफिस के पास धरना देते हुए।

कैमरा चालू होते ही धर्मेंद्र बदल जाते थे : श्रीराम राघवन

मुंबई/भाषा

फिल्म निर्देशक श्रीराम राघवन और अभिनेता धर्मेंद्र दोनों ही 'जॉनी गद्दार' के बाद एक साथ काम करने के इच्छुक थे और इसी के बाद 'इक्कीस' बनी जो धर्मेंद्र के करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई। राघवन का कहना है कि धर्मेंद्र ने इस 'युद्ध ड्रामा' में बेहतरीन काम किया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राघवन के लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति है, जिन्होंने धर्मेंद्र की फिल्में देखते हुए अपना बचपन बिताया है। उन्होंने बताया कि 'इक्कीस' का पोस्टर जारी करने के बाद धर्मेंद्र से जो प्यार मिला, उससे टीम खुश थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके निधन की खबर आ गई।

'पीटीआई-भाषा' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में राघवन ने कहा, जब मेरी फ्लाइट मुंबई उतरी तो मेरे निर्माता ने मुझे फोन किया और हम सीधे श्मशान घाट गए। रात में अचानक यह सब, आपको अभिभूत कर देता है। यह पूछे जाने पर कि क्या 'इक्कीस' धर्मेंद्र को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी? निर्देशक ने उम्मीद जताई कि यह सबके लिए एक यादगार साबित होगी।

उन्होंने कहा, उनकी भूमिका काफी अहम है, यह फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक बेहतरीन अभिनेता थे और उन्होंने फिल्म में अद्भुत काम किया है। राघवन ने याद किया, उन्हें (धर्मेंद्र को) बस कैमरे के सामने रहना पसंद था। 'जॉनी गद्दार' के दौरान वह पूरी तरह जोश से भरे रहते थे। 'इक्कीस' में भी ऐसा ही था। वह थोड़े थके हुए दिखते थे लेकिन कैमरा शुरू होते ही अचानक उनका दूसरा रूप सामने आ जाता था। धर्मेंद्र के प्रशंसक राघवन ने बताया कि उन्होंने 'जॉनी गद्दार' में उनकी पुरानी फिल्मों के गाने जोड़कर अभिनेता के योगदान को याद किया। राघवन को आज भी याद है कि 2007 में 'जॉनी गद्दार' के लिए धर्मेंद्र से संपर्क करते समय वह कितने घबराए हुए थे। राघवन ने याद किया कि धर्मेंद्र ने 'जॉनी गद्दार' के दूसरे भाग में कुछ बदलाव सुझाए थे और संवादों में भी योगदान दिया था। राघवन ने बताया, जब मैंने उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया तो उन्होंने इसका आनंद लिया।

उन्होंने कहा, दूसरा हाफ थोड़ा कमजोर है। बाद में हमने एक पुलिस अधिकारी का किरदार जोड़ा, जिसे गोविंद नामदेव ने निभाया। राघवन ने खुलासा किया कि 'जॉनी गद्दार' का प्रसिद्ध संवाद, शुरुआत मजबूरी से होती है, धीरे-धीरे मजबूरी जरूरत बन जाती है और फिर जरूरत आदत बन जाती है, खुद धर्मेन्द्र ने दिया था।

राघवन ने बताया कि 'जॉनी गद्दार' के बाद धर्मेंद्र अक्सर उनसे पूछते थे कि क्या उनके लिए कोई भूमिका मिली?

'नहीं पता था कि आखिरी मुलाकात होगी', अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से दुखी अर्चना पूरन सिंह

नई दिल्ली/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड गमगीन है। हर कोई अपने अंदाज में अभिनेता को याद कर रहा है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और कपिल शर्मा के शो में जज के तौर पर दिखने वाली अर्चना पूरन सिंह ने धर्मेंद्र को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने अभिनेता के साथ बिताए पलों को याद किया है। अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे धर्मेंद्र के साथ कपिल शर्मा शो के सेट पर डांस कर रही हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, शब्द कम पड़ रहे है, धरमजी जैसा कोई नहीं होगा। उस शाम, जब हम कपिल के शो पर कुछ मिनटों के लिए नाच रहे थे, मुझे लगा जैसे कायनात ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों और नेमतों में से एक दी हो। मुझे क्या पता था कि धरमजी से मेरी मुलाकात आखिरी बार होगी।

उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों से, मैं उनके गाने बार-बार सुन रही हूं, बस यह महसूस करने के लिए कि वो अभी भी यहां हैं। उनकी आंखों से उनकी दयालुता झलकती थी, और उनके हर शब्द से उनकी शालीनता झलकती थी। उनकी मुस्कान एक छोटे लड़के जैसी शर्मीली थी, सिर्फ वही किसी को हाथ मिलाकर गले मिलने वाला सुकून दे सकते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र से मिलना अर्चना पूरन सिंह के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि वे बचपन से उनसे मिलना चाहती थीं। उन्होंने आगे लिखा, धरमजी, बचपन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको देखने का मौका मिलेगा। आपके साथ परफॉर्म करना और आपसे बात करना मेरे लिए किसी सपने के पूरा होने के जैसा है।

एक्ट्रेस ने अभिनेता को लेकर काफी कुछ लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद फैंस की आंखें नम हो चुकी हैं। यूजर्स भी खुद को इस फीलिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह नेटफ्लिक्स के शो द कपिल शर्मा शो में जज के तौर पर दिख रही हैं, साथ ही वे अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जिसमें वे अपने परिवार और हाउसमेड्स से जुड़े वीडियो बनाती हैं।

एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारत ने जीता सिल्वर मेडल, रणदीप हुड्डा बोले-ये गर्व का पल

मुंबई/एजेन्सी

भारत ने एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ड्रेसेज स्पर्धा में रजत पदक (सिल्वर मेडल) अपने नाम किया। यह भारतीय घुड़सवारी खेल के लिए एक बड़ा और गर्व भरा क्षण माना जा रहा है। विजेता भारतीय टीम में चार प्रतिभाशाली घुड़सवार सुधीर सिंह, गौरव पुंडीर, दिव्यकृति सिंह और श्रुति वोरा शामिल थे। इस उपलब्धि पर फिल्म निर्माता और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। घुड़सवारी के शौकीन रणदीप सिंह हुड्डा ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, सिल्वर मिला...सुधीर सिंह, गौरव पुंडीर, दिव्यकृति सिंह, श्रुति वोरा...एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में हमें सिल्वर मेडल मिला। भारतीय घुड़सवारी खेल के लिए यह गर्व का पल है।

टीम को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के लिए टीम ड्रेसेज को बहुत-बहुत बधाई। भारतीय टीम पहले से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। रणदीप हुड्डा खुद एक कुशल घुड़सवार भी हैं और लंबे समय से इस खेल को बढ़ावा देते आ रहे हैं। फिल्मी करियर पर नजर डालें तो वह 'जाट', 'सरबजीत', 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर', 'किक', 'हाइवे', 'सुल्तान', और 'लाल रंग' जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। रणदीप एक्टिंग के साथ ही फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं। साल 2024 में रिलीज हुई हिंदी बायोपिक फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निर्देशन रणदीप ने किया है।

स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) के जीवन पर बनी फिल्म का निर्देशन करने के अलावा उन्होंने फिल्म का सह लेखन और सह-निर्माण भी किया है। सावरकर के क्रांतिकारी जीवन, ब्रिटिश जेल में काले पानी की सजा, हिंदुत्व की विचारधारा और देशभक्ति पर फोकस करती फिल्म में उन्होंने सावरकर की मुख्य भूमिका भी निभाई है।

धर्मेंद्र लीजेंड हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता : नीतू चंद्रा

गोवा/एजेन्सी

गरम मसाला और 13बी जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली नीतू चंद्रा अब फिल्म प्रोड्यूसर बन चुकी हैं। एक्ट्रेस बीते काफी समय से अपनी क्षेत्रीय फिल्म 'छठ' को प्रमोट कर रही हैं। उनकी फिल्म 'छठ' को आईएफएफआई में प्रदर्शित किया गया है। अब एनएफडीसी के मंच पर उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर खुलकर बात की और अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभिनेता कभी दुनिया छोड़कर नहीं जाते हैं। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र देओल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नीतू चंद्रा काफी इमोशनल नजर आई। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र जी लीजेंड हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता है। हम लोगों के लिए वे प्रेरणा हैं क्योंकि उनकी फिल्में ही देखकर हम बड़े हुए हैं। ऐसे कलाकार कभी दुनिया को छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी फिल्मों और काम से वे हमेशा हमारे बीच रहते हैं, भगवान उनकी आत्मा की शांति दें।भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी पर बात करते हुए नीतू चंद्रा ने कहा कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर मैं कह सकती हूं कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म हम जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहां हमारी फिल्मों को पहचान मिलती है। मैं यहां बिहार की एकलौती फिल्म छठ' को रिप्रेजेंट कर गर्व महसूस कर रही हूं।उन्होंने आगे कहा कि आईएफएफआई जैसे मंच भारतीय फिल्मों और क्षेत्रीय फिल्मों के बीच महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करते हैं।

रिद्धिमा ने शेयर किया 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का बीटीएस मोमेंट, कहा-'हमेशा साथ-साथ'

मुंबई/एजेन्सी

कपूर खानदान ने बॉलीवुड में कई दशकों से राज किया है। वहीं, इनके खाने के शौक और जिंदगी के पलों को जीवंत करते हुए नेटफ्लिक्स ने कपूर फैमिली की नई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' 21 नवंबर से स्ट्रीम की है। शो का बीटीएस मोमेंट रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उनके साथ नीतू कपूर और रीमा जैन नजर आ रही हैं। रिद्धिमा ने लिखा, हम हमेशा साथ-साथ हैं।

हर समय एक-दूसरे का साथ देते हुए। रिद्धिमा की पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। कई यूजर्स पोस्ट पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि शो में करिश्मा कपूर, करीना कपूर, जहान कपूर, अगस्त्य नंदा, आदर जैन, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, बबीता कपूर, रणबीर कपूर, अरमान जैन, नव्या नवेली नंदा समेत कई लोग नजर आ रहे हैं।

रिद्धिमा की बात करें तो उन्होंने कपूर खानदान से होने के बावजूद अपना करियर एक सफल ज्वेलरी और फैशन डिजाइनर और एक बिजनेसवुमन के तौर पर स्थापित किया।

उन्होंने 2006 में दिल्ली के व्यवसायी भरत साहनी से शादी की और उनकी एक बेटी समारा है। हालाकि, रिद्धिमा ने मनोरंजन की दुनिया में ओटीटी शो 'फेबुलस लाइव्स वर्सेज बॉलीवुड वाइव्स' से कदम रख चुकी हैं और वह जल्द ही नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ फिल्म 'डीकेएस' में अभिनय करती नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग शिमला के खूबसूरत लोकेशन्स पर हुई है। फिल्म के निर्देशक आशीष आर. मोहन हैं। अभिनेत्री नीतू कपूर की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म 'रिक्शावाला' (1973) थी। इसमें वह रणधीर कपूर के साथ नजर आई थीं। उन्होंने 'यादों की बारात', 'रफूचक्कर', 'दीवार', 'परवरिश', 'जानी दुश्मन', 'काला पत्थर', 'खेल खेल में', 'अमर अकबर एंथनी', 'याराना', 'धरम वीर', और 'कभी कभी' जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। 1983 में 'गंगा मेरी मां' के बाद उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया और 30 साल बाद 2009 में 'लव आज कल' से कमबैक किया। उनकी हालिया फिल्म 'जुगजुग जियो' थी।

ड्रिल एक्सरसाइज कर भाग्यश्री ने दिखाई अपनी फुर्ती

नई दिल्ली/एजेन्सी

मैंने प्यार किया में अपनी मासूमियत से फैंस के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री आज भी छोटे पर्दे पर सक्रिय हैं। अभिनेत्री रियलिटी शो में जज और स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिख चुकी है। आज भी 56 की उम्र में उनके चेहरे का ग्लो और फिटनेस बरकरार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 56 की उम्र में एक्ट्रेस अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम में पसीना बहा रही हैं। उन्होंने अब अपने फैंस की एनर्जी को टेस्ट करने के लिए एक चैलेंज दिया है। फिटनेस फ्रीक भाग्यश्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वे जिम में ड्रिल एक्सरसाइज करती दिख रही हैं। वीडियो में एक्ट्रेस फैंस को चैलेंज देते हुए दो ड्रिल करती हैं और कहती हैं कि चलिए देखते हैं कि आप कितने फुर्तीले हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, इसकी प्रैक्टिस से चपलता, गतिशीलता और ध्यान का परीक्षण किया जाएगा। मुझे हर एक्सरसाइज को करने में 7 सेकंड लगे। इसे आजमाएं और बताएं कि आपको कितना समय लगा। इसे रोजाना करें और अपनी गति बेहतर करने के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा करें। वीडियो में दो ड्रिल एक्सरसाइज करने में भाग्यश्री को 7 सेकंड का समय लगता है। इससे पता चलता है कि एक्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन और फुर्ती के मामले में कितनी ज्यादा एक्टिव हैं।

ये ड्रिल एक तरह की स्किल बेस्ड एक्सरसाइज है, जिससे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ गति और लचीलापन भी बढ़ता है। ये आमतौर पर धावकों और खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज के समय में इसे डेली वर्कआउट में भी शामिल कर लिया है। ये एक्सरसाइज दिल और मस्तिष्क दोनों के लिए फायदेमंद होती है। अगर 15 मिनट ड्रिल एक्सरसाइज की जाए तो ये हार्मोन संतुलन बनाने में मदद करता है और मूड को हल्का कर तनाव को कम करता है। ये एक्सरसाइज दिल की बीमारियों से बचने का आसान तरीका है।

तीन पत्नियों के बीच फंसे कपिल शर्मा, 'किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर रिलीज

नई दिल्ली/एजेन्सी

'किस किस को प्यार करूं' की सफलता के बाद कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा एक बार फिर तीन पत्नियों के पंगे में फंस चुके हैं। एक्टर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किस किस को प्यार करूं पार्ट-2' का धमाकेदार ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो गया, जिसमें कपिल इस बार तीन पत्नियों को मनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 'किस किस को प्यार करूं पार्ट-2' के ट्रेलर की शुरुआत सिंगर यो-यो हनी सिंह की आवाज के साथ होती है, जिसके बाद कपिल शर्मा चर्च के कन्फेशन रूम में जाकर अपने काले कारनामों को स्वीकारते हैं कि कैसे एक के बाद एक उन्होंने तीन शादियां की और अब चौथी की तैयारी है। इस बार कपिल क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं और तीनों को खुश रहने के लिए अलग-अलग अवतारों में दिख रहे हैं। फिल्म में कपिल शर्मा की पत्नियों का रोल त्रिधा चौधरी, आयशा खान और पारुल गुलाटी ने निभाया है।

एक्टर तीनों धर्मों की लड़कियों से शादी करके और दुनिया की नजरों से छिपाकर तीनों जिंदगियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आता है बड़ा ट्विस्ट और एंट्री होती है धाकड़ पुलिसवाले की। फिल्म को मजेदार बनाने के लिए अच्छे डायलॉग और कॉमिक टाइमिंग का ध्यान रखा गया है। कपिल शर्मा और मनजोत सिंह की जोड़ी कॉमेडी के मामले में कमाल कर रही है। ट्रेलर में लेने किसी और को जाता हूं, मिल कोई और जाती है और एक लड़की से प्यार करता हूं, उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना।

नेत्र शिविर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में 26 नवम्बर को अविशा स्माइल्स डेन्टल क्लिनिक में 32वां नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन नेमी कमला सिंघवी सेवा केंद्र, कुचेरा संगम ग्रुप, और एमएनआई हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया था। यह शिविर में महिपाल सिंघवी रणजीत शाह, सुंदरलाल, डॉ.योगिता और हितेश का योगदान रहा। जिसमें 36 लोगों ने निशुल्क आंखो की जांच कराई, 9 लोगों को चश्मे दिए जाएंगे।

संविधान दिवस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

इंडियन बैंक द्वारा चेन्नई स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया गया । इस अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बिनोद कुमार ने कार्यकारी निदेशकों तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन वरिष्ठ अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए शपथ लिया।

अंडरब्रिज निर्माण

दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल्ली डिवीजन ने वास्को डी गामा में एक नए रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी-292) पर काम 22 नवम्बर से शुरू कर दिया है। इसका मकसद वास्को शहर, डाबोलिम एयरपोर्ट, मडगांव और साउथ गोवा के बीच बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और फायर टेंडर की आवाजाही में रुकावट डालने वाली लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक की रुकावट को खत्म करना है। नया आरयूपी पहले वाले स्ट्रक्चर की जगह बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई सिर्फ़ 3.2 मीटर थी, जिससे इमरजेंसी सर्विस समेत लंबी गाड़ियों को 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। इस चक्कर की वजह से सेंट्रल और साउथ गोवा को जोड़ने वाले ज़रूरी रोड कॉरिडोर पर काफी भीड़ होती है।

आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रमादरहित साधना ही मुक्ति का उपाय : साध्वी भव्यगुणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के राजाजीनगर स्थित कानूंगा निवास पर विराजित साध्वी भव्यगुणाजी ने अपने दैनिक प्रवचन में बुधवार को कहा कि मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग जिम्मेदारियों के जाल में उलझकर गुजार देता है, जबकि ये सारी जिम्मेदारियां उसी पल समाप्त हो जाती हैं जब सांस की डोरी टूट जाती है। जीवन पेड़ के पत्ते जैसा है, बस एक झोंका और सब समाप्त, इसलिए भगवान कहते हैं समय को व्यर्थ मत गंवाओ, टालमटोल और बहानेबाजी ही प्रमाद है।

मनुष्यत्व और आर्यत्व दुर्लभ वरदान हैं, फिर भी लोग विषय-भोगों में उलझे रहते हैं। उन्होंने आगाह किया कि इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, इसलिए आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रमाद रहित साधना ही मुक्ति का उपाय है। विनय ही बहुश्रुतता की पहली शर्त है। बिना विनय कोई भी विद्वान नहीं बन सकता। सच्चा विद्यार्थी वही है जो गुरु के प्रति प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार रखे। साध्वी शीतलगुणाजी ने कहा कि ज्ञान पाना आसान है, पर ज्ञान को आचरण में उतारना कठिन है। जैसे धन कमाना सरल, उसका सद उपयोग कठिन वैसे ही ज्ञान को आत्मसात करना ही सच्चा विवेक है।

साधना किसी की ठेकेदारी नहीं है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां के न्यू धोबीपेट एसएस जैन संघ में राष्ट्रसंत श्री कमलमुनिजी कमलेश नेअपने प्रवचन में कहा कि महापुरुषों ने अक्षर ज्ञान डिग्री ज्ञान को पूरा ज्ञान नहीं माना है। बल्कि स्व और पर का भेद करने वाला ही सच्चा ज्ञान होता है।

दक्षिण जैन स्वाध्याय संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा की एक लौकिक ज्ञान होता है जो जीवन के चलाने के काम आता है, एक लोकोत्तर होता है जो आत्मा उत्थान के लिए काम आता है। उन्होंने कहा कि संत सूरदास जन्म से अंधे, अक्षर नहीं हुआ, दुनिया नहीं देखा तो भी आत्मा की अनुभूति से आत्म साधना करते हुए परमात्मा पद तक का आनंद लिया।

मुनि कमलेश ने बताया कि इंसान ही नहीं पशुओं को भी आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है। चंडकौशिक मेंढक आत्मा की अनुभूति करते हुए देवलोक गति को प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बने। साधना किसी की ठेकेदारी नहीं है। उसे किसी कर्मकांड की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। अपना अधिकार जताने वाले सबसे बड़े अज्ञानी और मिथ्यात्वी होते हैं। जैन संत ने कहा कि देहासक्ति त्याग किए बिना आत्म शक्ति का साक्षात्कार नहीं हो सकता, उसके बिना साधना में प्रवेश भी नहीं कर सकता।

दक्षिण स्वाध्याय संघ के अध्यक्ष लाभचंद खारीवाल एवं कमला मेहता ने कहा कि सद्साहित्य के माध्यम से सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है बच्चों के संस्कारों हेतु चार पुस्तकों का विमोचन हुआ। न्यू धोबीपेट संघ के गौतम चंद मेहता, ज्ञानचंद संचेती, सज्जन चौरड़िया, ललित मकाना, महिला मंडल आशा दुग्गड़, चंदनबाला पावेचा युवक मंडल सहित सभी ने गुरुओं का अभिनंदन किया।

मुल्क, मज़हब, मानवता की जरूरत है समान नागरिक संहिता : नकवी

नयी दिल्ली/भाषा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि आजादी का अमृत काल, समान नागरिक कानून पर संवैधानिक दिशानिर्देश को अंगीकार करने का अवसर है। उन्होंने संविधान दिवस के अवसार भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में यह भी कहा कि समान नागरिक कानून, पूरे मुल्क के लिए है, किसी मजहब के लिए नहीं है तथा एक कंट्री, एक क़ानून भारत की ज़रूरत है। नकवी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मूल संवैधानिक भावना और समावेशी सोच को सशक्त करने के लिए समान नागरिक संहिता मुल्क, मज़हब, मानवता की जरूरत है।

संवैधानिक-समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार करने वाले न तो मुल्क के हितैषी हैं न किसी मज़हब के। भय-भ्रम के गटर पर भरोसे का शटर लगा कर, संविधान की ताक़त को साज़िशी आफ़त से बचाना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान की समावेशी, सर्वस्पर्शी सोच बहुसंख्यकों के संस्कार, संकल्प, संस्कृति का नतीजा है। नकवी का कहना था, 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किए गए भारतीय संविधान की जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष भावना आज भी सशक्त और सुरक्षित है।

देवी उत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूर के श्री साई बडावणे निवेशन द्वार क्षेमाभिवृदि संघ, साईं नगर मंगनहली द्वारा आयोजित अन्ना अण्णम्मा देवी महोत्सव में मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित करते हुए अन्नदान कार्यक्रम में सेवा प्रदान की। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।

सद्गुरु एकेडमी 'इनसाइड' की मेजबानी करेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बटूर। यहां सद्गुरु एकेडमी अपने सालाना बिज़नेस लीडरशिप कार्यक्रम 'इनसाइट : दि डीएनए ऑफ सक्सेस' के 14वें संस्करण की मेज़बानी करेगी। बिज़नेस के मालिकों और सी-सूट एग्जीक्यूटिव्स के लिए यह कार्यक्रम, 27 से 30 नवंबर ईशा योग सेंटर में होगा। सद्गुरु एकेडमी द्वारा आयोजित इस सालाना कार्यक्रम में, बिज़नेस को बढ़ाने और अपनी आंतरिक क्षमताओं को निखारने के विज्ञान पर गहराई से चर्चा की जाती है। चार दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की परिकल्पना और नेतृत्व ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, सद्गुरु ने किया है।

सद्गुरु और दूसरे वक्ता के सत्रों के अलावा, इस कार्यक्रम में कार्यशालाएं, लाइव केस स्टडीज़, वन-ऑन-वन सत्र और साथ ही योग और ध्यान भी शामिल हैं। इस साल के संस्करण में कई दिग्गज 'रिसोर्स लीडर्स' और वक्ता शामिल होंगे। इनमें यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य, लॉर्ड करन बिलिमोरिया; सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरपर्सन, माधबी पुरी बुच; हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन, नितिन परांजपे; कॉन्शियस कैपिटलिज्म खपल. के को-फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस, राज सिसोदिया; ऐस-वेक्टर और टाइटन कैपिटल के को-फाउंडर, रोहित बंसल; देहात के सीईओ और को-फाउंडर, शशांक कुमार; और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर और 'सद्गुरु सेंटर फॉर ए कॉन्शियस प्लैनेट' के डायरेक्टर, डॉ. बाल सुब्रमण्यम शामिल हैं।

अंतरिक्ष बहुत मज़ेदार जगह, लेकिन भारहीनता के कारण रहती है भ्रम की स्थिति : शुभांशु शुक्ला

भुवनेश्वर/भाषा

अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की कमी (भारहीनता) के कारण भ्रम की स्थिति रहती है। यहां स्कूली छात्रों से बातचीत करते हुए शुक्ला ने कहा, अंतरिक्ष मज़ेदार जगह है, क्योंकि वहां आपके शरीर समेत सब कुछ तैर रहा होता है। हमारे लिए, वहां ताकत लगाये बिना बड़े आकार के सामान को इधर-उधर ले जाना भी बहुत आसान था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के अंदर उस मज़ेदार पल का एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए बताया कि मजे मजे में, अंतरिक्ष यात्री उनमें से किसी एक साथी को गेंद की तरह इस्तेमाल करते थे और एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर धकेल कर खेलते थे। शुक्ला ने कहा कि हालांकि, शरीर के लिए अंतरिक्ष की परिस्थितियों में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री शुक्ला ने कहा, ऊपर-नीचे समझ पाना बहुत मुश्किल था... मेरा दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था। तीन-चार दिनों तक मुझे भूख ही नहीं लगी क्योंकि हमारे पेट में भी सब कुछ तैर रहा होता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में, कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं तथा चूंकि मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं होता, इसलिए मांसपेशियां बहुत तेजी से क्षीण होती हैं। ग्रुप कैप्टन ने बताया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनकी 4.5 किलोग्राम से अधिक मांसपेशियां कम हो गई थीं।

उन्होंने कहा कि शरीर धीरे-धीरे नये वातावरण का आदी हो जाता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष से धरती पर लौटता है, तो पूर्ववत होना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको उन बातों पर भी विश्वास दिला देता है जो जरूरी नहीं कि सच हों। यह कहते हुए कि भारत सही राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां भविष्य में उसे काफी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की आवश्यकता होगी, शुक्ला ने कहा, हमें इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिज्ञासा और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। शुक्ला ने छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, जब हम अंतरिक्ष अन्वेषण की बात करते हैं, तो हमारे पास उन समस्याओं को सुलझाने का कौशल होता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। इसके लिए सबसे आवश्यक कौशल, समस्या-समाधान कौशल है।

उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने सपनों को केवल अंतरिक्ष यात्री बनने तक ही सीमित न रखें, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पोशाक डिजाइन से लेकर पोषण तक, बहुत संभावनाएं हैं। अपनी प्रस्तुति के दौरान, शुक्ला ने आईएसएस से पृथ्वी, भारत और सूर्योदय के दृश्य दिखाने वाले वीडियो भी साझा किए, जो उन्होंने खुद बनाए थे। सभा को संबोधित करते हुए, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना के तहत अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी का मार्ग अपनाकर योजना का लाभ उठाएं और शुभांशु शुक्ला जैसा व्यक्ति बनें तथा विकसित भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनें।

इंडोनेशिया : सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन, मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हुई

मेदान (इंडोनेशिया)/एपी

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित दर्जनों लोगों के बचाव अभियान के दौरान, बचावकर्मियों ने कई और शव बरामद किए हैं। इसके साथ ही, इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जबकि छह अन्य व्यक्ति अब भी लापता हैं।

राष्ट्रीय पुलिस ने एक बयान में कहा कि पिछले सप्ताह हुई मानसूनी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गईं हैं और बाढ़ से इलाके में तबाही मच गई। इस घटना के बाद बचाव दल, उत्तरी सुमात्रा प्रांत के छह जिलों में प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.